मूल्य 50/-

पंचायत 24

वर्ष-01 अंक-01 जुलाई, 2026

हिंदी मासिक पत्रिका

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट :
भूमि से बुलंदियों तक
ऐतिहासिक उड़ान

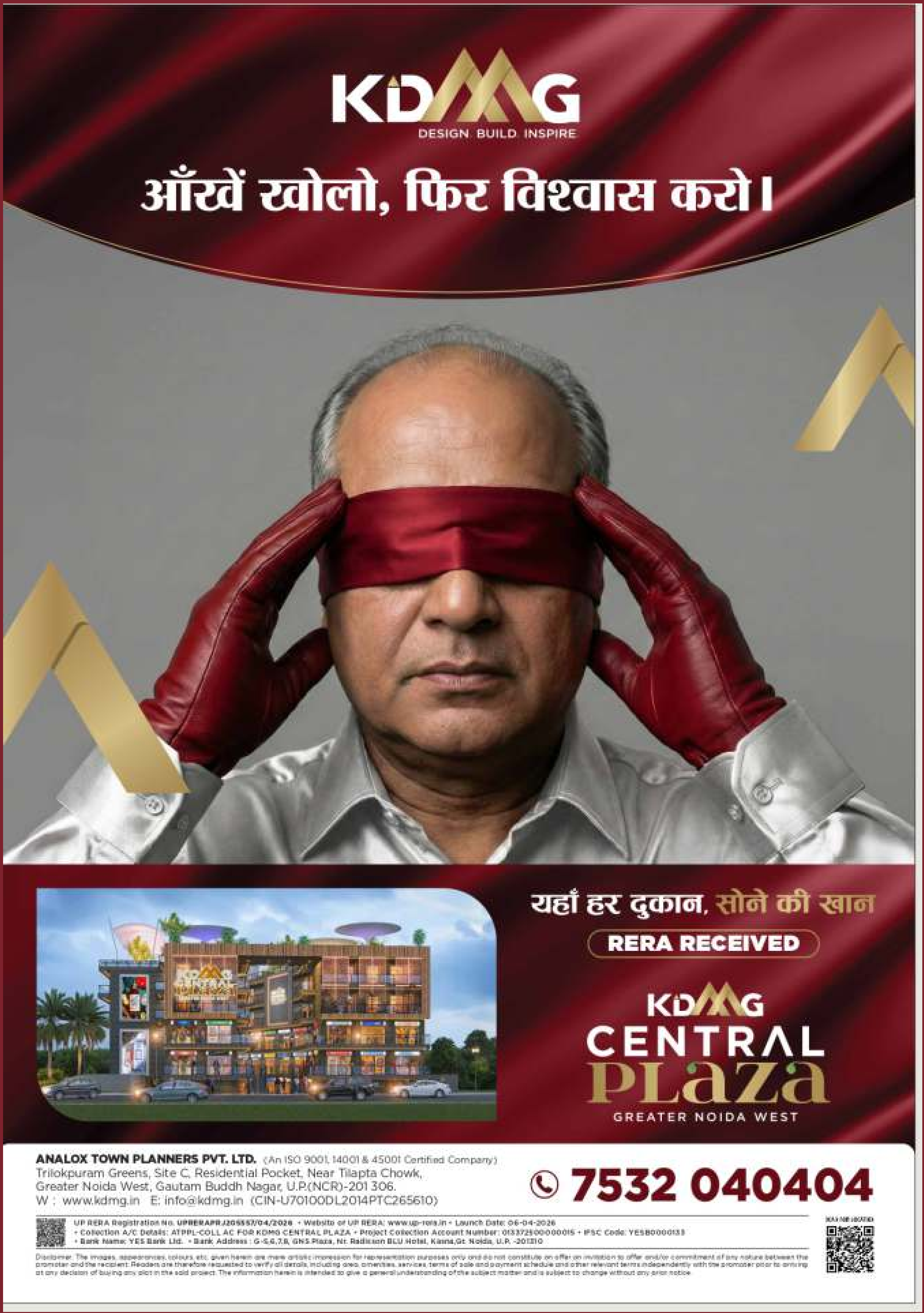
KDMG
DESIGN BUILD INSPIRE
आँखें खोलो, फिर विश्वास करो।
यहाँ हर दुकान, सोने की खान
RERA RECEIVED
KDMG
CENTRAL
PLAZA
GREATER NOIDA WEST
ANALOX TOWN PLANNERS PVT. LTD. (An ISO 9001, 14001 & 45001 Certified Company)
Trilokpuram Greens, Site C, Residential Pocket, Near Tilapta Chowk,
Greater Noida West, Gautam Buddh Nagar, U.P.(NCR)-201 306.
W : www.kdmg.in E: info@kdmg.in (CIN-U70100DL2014PTC265610)
7532 040404

KDMG
DESIGN. BUILD. INSPIRE.
आँखें खोलो, फिर विश्वास करो।
एक टाउनशिप, अनगिनत अवसर
AUTHORITY APPOVED
KDMG
Trilokpuram
Greens
GREATER NOIDA WEST
ANALOX TOWN PLANNERS PVT. LTD. (An ISO 9001, 14001 & 45001 Certified Company)
Trilokpuram Greens, Site C, Residential Pocket, Near Tilapta Chowk,
Greater Noida West, Gautam Buddh Nagar, U.P.(NCR)-201 306.
W : www.kdmg.in E: info@kdmg.in (CIN-U70100DL2014PTC265610)
7532 040404

पंचायत 24

वर्ष-01 अंक-01 जुलाई, 2026

संरक्षक मंडल

नरेंद्र कुमार शर्मा

श्रीचंद शर्मा

चैयरमेन केशव माधव इंस्टिट्यूट

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य)

डॉ नवीन कुमार

चैयरमेन नवीन अस्पताल समूह

डॉ महेंद्र नागर

चैयरमेन नागर हॉस्पिटल

विनोद गोयल

निदेशक शैफाली स्कूल समूह एवं

प्रबंधक अग्रसेन इंटर कॉलेज दादरी

योगेंद्र शर्मा

अध्यक्ष फोनरवा, नोएडा

सरबजीत

चैयरमेन आईआईए ग्रेटर नोएडा चेप्टर

प्रधान संपादक

डॉ देवेंद्र कुमार शर्मा

सलाहकार सम्पादक

राजेश बैरागी

प्रबंधक

हिमानी शर्मा

विधिक सलाहकार

ममता शर्मा

अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट

रजनीश यादव

मनु बैरागी

प्रवीण शर्मा

स्वामी प्रकाशक संपादक डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा मुद्रक मनोज वत्स स्वामी वत्स ऑफसेट मकान नंबर 25 मुद्दा हाउस ऑफ सी ब्लॉक बारात घर चौड़ा रघुनाथपुर सेक्टर 22 गौतम बुध नगर उत्तर प्रदेश 201301 से मुद्रित एवं पुराना नेशनल हाईवे 91, चितेहरा दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0-203207 से प्रकाशित

संपादक : डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा

किसी भी वाद विवाद से निपटने के लिए जिला गौतमबुद्धनगर मान्य होगा

10 दो दशक के सपने से औद्योगिक क्रांति तक...

28 साक्षात्कार : व्यक्ति विशेष

उत्तर प्रदेश की ट्रिलियन डॉलर 38

डा. देवेन्द्र कुमार शर्मा

शब्दों के माध्यम से समाज की नब्ज़ टटोलने का एक विनम्र प्रयास

प्रिय पाठकों,

जब कोई नया प्रकाशन जन्म लेता है, तो वह केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता, बल्कि अपने समय, समाज और सरोकारों का एक जीवंत दस्तावेज़ बनकर सामने आता है। 'पंचायत 24' भी ऐसा ही एक विनम्र प्रयास है—एक ऐसी मासिक पत्रिका, जो केवल समाचारों को दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय पक्षों को समझने और समझाने के उद्देश्य से आपके बीच आई है।

आज सूचना का विस्फोट है। मोबाइल की एक स्क्रीन पर हजारों खबरें हर दिन हमारे सामने आती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि खबरों की इस भीड़ में संदर्भ खो रहे हैं, संवेदनाएँ खो रही हैं और गहराई कहीं पीछे छूटती जा रही है। हर व्यक्ति के पास जानकारी है, परंतु समझ का अभाव है; समाचार हैं, पर विश्लेषण का संकट है।

इसी शून्य को भरने का प्रयास है—पंचायत 24।

यह पत्रिका केवल घटनाओं का ब्यौरा नहीं देगी, बल्कि उन घटनाओं के पीछे के कारण, उनके दूरगामी प्रभाव और समाज पर पड़ने वाले परिणामों की पड़ताल भी करेगी। हमारा मानना है कि पत्रकारिता का दायित्व केवल यह बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी समझाना है कि क्यों हुआ और उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पत्रिका सत्ता और समाज, विकास और विस्थापन, परंपरा और परिवर्तन, गाँव और शहर, किसान और उद्योग, राजनीति और जनजीवन—इन सभी के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करेगी।

यहाँ आपको केवल सुर्खियाँ नहीं मिलेंगी, बल्कि—

- जमीनी रिपोर्ट और खोजपरक लेख,
- ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर,
- विकास परियोजनाओं का सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण,
- किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों की गंभीर पड़ताल,
- इतिहास, साहित्य, संस्कृति और लोक परंपराओं पर विशेष सामग्री,
- राजनीति के शोर से परे तथ्यों और तर्कों पर आधारित विश्लेषण,
- और सबसे बढ़कर, समाज के उन लोगों की कहानियाँ, जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में जगह नहीं बना पाते।

हमारा मानना है कि भारत की आत्मा केवल संसद में नहीं, पंचायत में भी बसती है; विकास केवल महानगरों में नहीं, गाँवों की पगडंडियों पर भी आकार लेता है।

इसीलिए 'पंचायत 24' ने अपने नाम में ही अपनी दृष्टि को समाहित किया है। हमारे लिए पंचायत केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि संवाद, सहभागिता और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। और 24 केवल समय का अंक नहीं, बल्कि समाज के प्रति चौबीसों घंटे जागरूक रहने की पत्रकारिता की प्रतिबद्धता है। हम किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं, बल्कि एक प्रश्नाकुल मन और संवेदनशील दृष्टि के साथ आपके बीच आए हैं। हमारा उद्देश्य किसी विचार को थोपना नहीं, बल्कि विचारों को जन्म देना है; किसी निष्कर्ष को आरोपित करना नहीं, बल्कि पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करना है।

हमें विश्वास है कि 'पंचायत 24' केवल पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि महसूस की जाएगी; केवल सूचना नहीं देगी, बल्कि चिंतन को जन्म देगी; केवल घटनाएँ नहीं बताएगी, बल्कि समाज की नब्ज़ टटोलने का माध्यम बनेगी। इस प्रथम अंक को आपके हाथों में सौंपते हुए हम विश्वास दिलाते हैं—हम शब्दों की गरिमा, तथ्यों की पवित्रता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कभी समझौता नहीं करेंगे। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूँजी है और आपकी सहभागिता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसी पत्रकारिता की यात्रा प्रारंभ करें, जहाँ खबरें केवल पढ़ी न जाएँ, बल्कि समझी भी जाएँ; जहाँ विचार केवल व्यक्त न हों, बल्कि समाज को दिशा भी दें।

बच्चों का मन, संस्कार और समाज

खोड़ा और जेवर की घटनाओं से उठते गंभीर प्रश्न

समाज में घटित होने वाली कुछ घटनाएं केवल आपराधिक मामले नहीं होतीं, वे उस सामाजिक और वैचारिक वातावरण का दर्पण भी बन जाती हैं जिसमें नई पीढ़ी तैयार हो रही होती है। गाजियाबाद के खोड़ा में 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की निर्मम हत्या और गौतमबुद्धनगर के जेवर क्षेत्र के बनवारीवास गांव में गोपाल शर्मा नामक 15 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु ऐसी ही दो घटनाएं हैं, जिन्होंने समाज को झकझोरने के साथ-साथ बच्चों के संस्कार, शिक्षा, संगति और मानसिक निर्माण को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

खोड़ा की घटना में आरोप है कि एक किशोर को उसके परिचित ने मिलने के लिए बुलाया। विवाद के दौरान उस पर चाकू से हमला किया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर, जेवर की घटना में पुलिस जांच के अनुसार एक नाबालिग की मृत्यु के पीछे गलत संगत, आपसी रंजिश और गैर-जिम्मेदार व्यवहार की भूमिका सामने आई। दोनों घटनाओं का स्वरूप अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, आरोपी अलग हैं, लेकिन दोनों घटनाओं में एक समानता है—पीड़ित और आरोपी सभी किशोर या युवा आयु वर्ग से जुड़े हैं।

यही वह बिंदु है जहां समाज को केवल अपराध की घटना पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके कारणों की ओर भी देखना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि किशोरावस्था, जो सपनों, संभावनाओं और भविष्य निर्माण की उम्र मानी जाती है, वहां हिंसा, आक्रामकता, असहिष्णुता और संवेदनहीनता जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं?

किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व तीन प्रमुख संस्थाओं से निर्मित होता है—परिवार, शिक्षण संस्थान और सामाजिक वातावरण। परिवार बच्चे को जीवन के प्रारंभिक संस्कार देता है। वहीं से वह प्रेम, सम्मान, सहिष्णुता, अनुशासन और संवेदनशीलता सीखता है। इसके बाद स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान उसकी सोच को विकसित करते हैं। मित्र-मंडली और सामाजिक परिवेश उस सोच को व्यवहार में बदलते हैं। यदि इन तीनों में कहीं भी गंभीर कमी आ जाए तो उसका प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ना स्वाभाविक है। खोड़ा की घटना ने एक बार फिर धार्मिक पहचान, कट्टरता और वैचारिक असहिष्णुता को लेकर बहस छेड़ दी है। वहीं जेवर की घटना ने गलत संगत, नशे और नैतिक पतन की समस्या को सामने रखा है। दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखने पर एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि समस्या का मूल कारण केवल धर्म, केवल परिवार या केवल शिक्षा नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में मानवीय मूल्यों की जगह संकीर्ण सोच, हिंसक प्रवृत्तियां या गैर-जिम्मेदार व्यवहार प्रवेश कर जाते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को सबसे पहले इंसान बनना सिखाया जाए। उन्हें यह सिखाया जाए कि किसी भी व्यक्ति का जीवन, सम्मान

और अधिकार उसके धर्म, जाति, भाषा या पहचान से ऊपर हैं। उन्हें यह समझाया जाए कि असहमति का उत्तर हिंसा नहीं, संवाद होता है। मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मनुष्यता सर्वोपरि है।

इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न संस्थागत धार्मिक शिक्षा को लेकर भी उठता है। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था और आध्यात्मिक विश्वास का विषय है। लेकिन जब नाबालिग बच्चों को संगठित रूप से ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें तर्क, प्रश्न और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता, तब उनके मन में कुछ मान्यताएं स्थायी रूप से स्थापित हो सकती हैं। बाल मन स्वभावतः ग्रहणशील होता है, आलोचनात्मक नहीं। वह सुनता अधिक है, परखता कम है। जब तक वह स्वतंत्र रूप से तर्क करने की स्थिति में पहुंचता है, तब तक अनेक विचार उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके होते हैं।

इसी आधार पर यह मत सामने आता है कि नाबालिगों के लिए संस्थागत धार्मिक शिक्षा पर पुनर्विचार होना चाहिए। बच्चों को पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा, मानवाधिकार, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता की शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक ज्ञान परिवार के स्तर पर सांस्कृतिक और पारिवारिक परंपरा के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की वैचारिक श्रेष्ठता, असहिष्णुता या विभाजनकारी सोच को बच्चों के मन में स्थान नहीं मिलना चाहिए।

यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि किसी एक अपराध के आधार पर किसी पूरे धर्म, समुदाय या शिक्षण व्यवस्था को दोषी ठहराना न तो उचित है और न ही न्यायसंगत। अपराधी की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है। लेकिन समाज की जिम्मेदारी सामूहिक होती है। यदि बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो हमें उन परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा जो बच्चों को हिंसा, कट्टरता, नशे, अपराध या असामाजिक व्यवहार की ओर धकेल रही हैं।

दुर्भाग्य से आज शिक्षा का बड़ा हिस्सा केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित होता जा रहा है। नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। परिणामस्वरूप तकनीकी रूप से शिक्षित लेकिन भावनात्मक और नैतिक रूप से कमजोर पीढ़ी तैयार होने का खतरा बढ़ रहा है।

खोड़ा और जेवर की घटनाएं हमें यही चेतावनी देती हैं कि यदि हम आने वाली पीढ़ी के मानसिक और नैतिक निर्माण पर गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे तो केवल कानून और पुलिस व्यवस्था से समस्या का समाधान नहीं होगा। अपराध होने के बाद दंड देना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें अपराधी मानसिकता विकसित ही न हो।

समाज, परिवार, विद्यालय और सरकार—सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा और संस्कार मिलें जो उन्हें पहले एक अच्छा इंसान बनाएं, फिर सफल नागरिक। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके हथियारों, इमारतों या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र में होती है। और चरित्र का निर्माण बचपन से ही शुरू होता है।

खोड़ा और जेवर की घटनाएं केवल दो परिवारों की त्रासदी नहीं हैं; वे पूरे समाज के लिए एक चेतावनी हैं। प्रश्न यह नहीं है कि इन घटनाओं के आरोपी कौन थे। प्रश्न यह है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा समाज, कैसी शिक्षा और कैसे संस्कार देने जा रहे हैं। ■

राजकुमार भाटी विवाद और उत्तर प्रदेश की नई सोशल इंजीनियरिंग

लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग केवल चुनावी अंकगणित से नहीं, बल्कि सामाजिक रसायनशास्त्र से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां चुनावी सफलता अक्सर सामाजिक गठबंधनों और जातीय समीकरणों की मजबूती पर निर्भर करती है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ प्रदेश एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की नई प्रयोगशाला बनता दिखाई दे रहा है।

एक ओर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे अपने सामाजिक गठबंधन को बनाए रखने में जुटी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नए राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में मिले अपेक्षाकृत बेहतर परिणामों ने समाजवादी पार्टी को यह विश्वास दिलाया है कि पीडीए का मॉडल भाजपा के लिए कड़ी चुनौती देने में सक्षम है।

इसी पृष्ठभूमि में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के हालिया बयानों को देखा जा रहा है। उनके कुछ विवादित वक्तव्यों ने राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस को जन्म दिया। इन बयानों को लेकर न केवल भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया, बल्कि कई स्थानों पर विरोध, शिकायतें और कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिली। हालांकि, इन टिप्पणियों के कारण पार्टी के भीतर भी असहजता पैदा हुई और कई नेताओं ने सार्वजनिक नाराजगी व्यक्त की।

राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि ऐसे बयान केवल व्यक्तिगत टिप्पणी भर नहीं होते, बल्कि अक्सर व्यापक राजनीतिक संदेश का हिस्सा बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह पीडीए के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विश्वास और राजनीतिक एकजुटता को मजबूत करे। इसके लिए सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, भागीदारी और राजनीतिक सम्मान जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। दूसरी ओर भाजपा इन घटनाओं को अपने पक्ष में अवसर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भाजपा का तर्क है कि ऐसे बयान उसके पारंपरिक सामाजिक समर्थन आधार को समाजवादी पार्टी से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व लगातार हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को प्रमुखता दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का "बटोगे तो कटोगे" वाला राजनीतिक संदेश भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। इस संदेश के माध्यम से भाजपा जातीय पहचान से ऊपर उठकर व्यापक हिंदू एकता का आह्वान करती है। वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक प्रतिनिधित्व और पीडीए की राजनीतिक शक्ति को अपनी रणनीति का केंद्र बना रही है।

यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब केवल विकास बनाम विकास का संघर्ष नहीं है। इसके समानांतर सामाजिक पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक विमर्श की भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। राजकुमार भाटी प्रकरण इसी व्यापक राजनीतिक संघर्ष का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। समाजवादी पार्टी की ओर से 85 बनाम 15(बहुसंख्यक ओबीसी/एससी/एसटी जातियां बनाम अल्पसंख्यक सवर्ण जातियां) वाले बयान पीडीए में शामिल की गई जातियों की सवर्ण जातियों के प्रति अशंका के भाव को पुष्ट करते है और यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते है सवर्ण जतियों से उन्हें न्याय तभी मिल सकता है जब वह पीडीए का हिस्सा होंगी। अर्थात उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश है कि समीजवादी पार्टी ही उनकी सच्ची हितैषी है भले ही इतिहास कुछ भी रहा हो । वास्तव में ऐसे बयान पीडीए के सोशल इंजीनियरिंग के अंकगणित के साथ भरोसे वाली कैमिस्ट्री को मजबूत करने का प्रयास है।

हालांकि अंततः चुनाव केवल नारों और बयानों से नहीं जीते जाते। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, निवेश और युवाओं के अवसर जैसे मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जनता बीती सरकार और वर्तमान सरकार के कामों को कसौटी पर परखती है। इसलिए 2027 का चुनाव यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता सामाजिक गठबंधनों की राजनीति को अधिक महत्व देती है या विकास और शासन के दावों को।स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हिंदुत्व आधारित सोशल इंजीनियरिंग और समाजवादी पार्टी की पीडीए आधारित सोशल इंजीनियरिंग के बीच संघर्ष आने वाले वर्षों में और तेज होगा। राजकुमार भाटी विवाद जैसे घटनाक्रम इस संघर्ष की केवल झलक हैं। असली फैसला अंततः जनता के हाथ में होगा, जो यह तय करेगी कि प्रदेश की राजनीति की अगली दिशा कौन सा सामाजिक और राजनीतिक मॉडल निर्धारित करेगा। ■

समाज का दहकता सच

मर्यादाओं की कसौटी पर बिखरते गृहस्थी के रिश्ते

गौतम बुद्ध नगर (ग्रेटर नोएडा) के शांत गांवों से हाल ही में उठी तीन चीखों ने पूरे समाज की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। सिरसा गांव का निक्की भाटी हत्याकांड, जलपुरा का दीपिका नागर हत्याकांड और घोड़ी बछेड़ा का मोनिका नागर मामला—ये तीनों घटनाएं केवल आपराधिक आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने के सड़ने का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। एक तरफ जहां बेटियां दहेज रूपी दानव की भेंट चढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता और सामाजिक मर्यादाओं के बीच का असंतुलन भी हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ रहा है इन तीनों मामलों में एक बात समान रूप से उभर कर सामने आई है—'दहेज का लालच'। सिरसा गांव में एक विवाहिता को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया गया। जलपुरा में महज 14 महीने पहले ब्याही गई एक उच्च शिक्षित बेटी को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। घोड़ी बछेड़ा में एक नवविवाहिता का शव आधी जली हुई हालत में सड़क किनारे मिला। शादियों में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां देने के बावजूद फॉर्च्यूनर और करोड़ों रुपये की नगदी की मांग न रुकना यह दर्शाता है कि हमारा समाज आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन मानसिक रूप से बेहद संकीर्ण हो चुका है। बहू को लक्ष्मी मानकर घर लाने वाला लड़का पक्ष जब उसे चंद रुपयों और गाड़ियों के लिए प्रताड़ित करता है, तो वह केवल एक कानून नहीं तोड़ता, बल्कि इंसानियत का कत्ल करता है। समाज को मिलकर इस दहेज रूपी दानव का बहिष्कार करना ही होगा।

इस कड़वे सच का दूसरा पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वैवाहिक जीवन दो पहियों की गाड़ी है, जो केवल तभी चल सकती है जब दोनों पहिये एक ही दिशा में और मर्यादा के भीतर चलें। आज के दौर में जहां लड़कों को महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें बराबरी का दर्जा देने के संस्कार देने की सख्त जरूरत है, वहीं बेटियों को भी यह समझना होगा कि आधुनिकता का मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं है।जब कोई लड़का पक्ष किसी लड़की को बहू बनाकर अपने घर लाता है, तो उसकी कुछ स्वाभाविक और पवित्र अपेक्षाएं होती हैं। वह चाहता है कि जो बेटी उनके घर आ रही है, वह एक अच्छी बहू, एक समर्पित पत्नी और भविष्य में एक अच्छी मां साबित हो। लेकिन जब लड़की द्वारा इन प्राथमिकताओं को ताक पर रखकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की होड़, दिन-रात रील (Reels) बनाने की जिद और आभासी दुनिया की चकाचौंध को असली जिंदगी से ऊपर रख दिया जाता है, तो रिश्तों में दरार आनी तय है। आधुनिक समाज में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना परिवार, मान-मर्यादा और आपसी संवाद से बड़ा हो जाता है, तो वह घरेलू क्लेश का कारण बनता है। सिरसा गांव के मामले में भी यह बात सामने आई कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने और रील्स को लेकर विवाद गहराया था। बेटियों को यह समझना होगा कि शादी के बाद एक नए परिवार का हिस्सा बनना केवल अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि कर्तव्यों का निर्वहन भी है। सोशल मीडिया की आभासी तारीफें कभी भी एक सुखी परिवार और मानसिक शांति का विकल्प नहीं हो सकतीं। यदि शादियां केवल रील्स और रईसी के प्रदर्शन तक सीमित रह जाएंगी, तो सामाजिक संबंधों का आधार कमजोर होना निश्चित है।

यदि हमें समाज को इन दर्दनाक हत्याकांडों और आत्महत्याओं से बचाना है, तो एक दोतरफा प्रयास की आवश्यकता है। लड़का पक्ष के लिए आवश्यक है कि बेटियों को सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि अपने घर की गरिमा समझें। दहेज की भूख को छोड़ें और घरेलू हिंसा व उत्पीड़न पर पूर्ण विराम लगाएं। वहीं, लड़की पक्ष और बेटियों के लिए को भी भी इस बात को समझने कि आवश्यकता है कि शादी के बाद अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। आधुनिक बनें, लेकिन अपनी जड़ों, संस्कारों और पारिवारिक मर्यादाओं को न भूलें।अगर यह संतुलन नहीं बना, तो न केवल दो परिवारों के संबंध बिगड़ेंगे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बिखर जाएंगी। समय आ गया है कि समाज कानून के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपनी मर्यादाओं को तय करे और रिश्तों की पवित्रता को पुनर्स्थापित स्थापित करें। ■

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

दो दशक के सपने से औद्योगिक क्रांति तक जिसने बदल दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर

जेवर से उड़ान भरता नया भारत: खेतों से वैश्विक निवेश केंद्र बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जेवर क्षेत्र कभी दूर-दूर तक फैले खेतों, छोटे गांवों और सीमित आर्थिक गतिविधियों वाला इलाका माना जाता था। आज यही क्षेत्र देश की सबसे महत्वाकांक्षी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में से एक—नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट—के कारण भारत के उभरते औद्योगिक, निवेश और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। पहली वाणिज्यिक उड़ान के साथ यह परियोजना केवल एक हवाई अड्डे का संचालन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक इतिहास में एक नए युग की औपचारिक शुरुआत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले चरण के उद्घाटन के साथ यह स्पष्ट हो गया कि जेवर अब केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की नई विकास गाथा का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। लगभग 11,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस एयरपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। पूर्ण विकास के बाद इसकी वार्षिक क्षमता लगभग सात करोड़ यात्रियों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिससे यह देश के सबसे बड़े विमानन एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रों में शामिल होगा।

दो दशक पहले बोया गया विकास का बीज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि लगभग ढाई दशक तक चले दूरदर्शी प्रयासों, नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की कहानी है।

साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में पहली बार दिल्ली-एनसीआर के लिए दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की अवधारणा सामने आई। उस समय यह महसूस किया गया कि भविष्य में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एक वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता होगी।

इसके बाद वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इसे "ताज एविएशन हब" के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि राजनीतिक परिवर्तन,

नीतिगत जटिलताएं और कानूनी बाधाओं के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

चुनौतियों से भरा सफर

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सामने अनेक कठिनाइयां थीं। लंबे समय तक यह नीति प्रभावी रही कि दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक स्वीकृतियां, पर्यावरणीय मंजूरियां, व्यावसायिक हित तथा हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी बड़ी चुनौतियां बने रहे।

भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों की आशंकाएं, मुआवजा और पुनर्वास जैसे मुद्दे भी समय-समय पर सामने आए। इतनी विशाल परियोजना को धरातल तक पहुंचाना किसी भी सरकार और प्रशासन के लिए आसान कार्य नहीं था।

2014 के बाद बदली तस्वीर, 2017 के बाद मिली निर्णायक गति

साल 2014 में केंद्र में भजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकर बनने के बाद इस परियोजना की तस्वीर बदल शुरू हो गई। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया। उन्होंने इस परियोजना में निजी तौर पर रुचि दिखाते हुए अहम भूमिका निभाई।

परियोजना को वास्तविक गति तब मिली जब केंद्र और उत्तर प्रदेश में समान दलों की सरकार बनी और समन्वित रूप से निर्णय प्रक्रिया तेज हुई। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में योगीदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसे राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया।

केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरियां मिलने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होने, पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त होने तथा वित्तीय मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद परियोजना ने तेजी से आकार लेना शुरू किया। वर्ष 2020 में स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठित कंपनी Zurich Airport International AG (ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल) की सहयोगी कंपनी को परियोजना का विकासकर्ता चुना गया और इसके बाद निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू हुआ। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और कुछ ही वर्षों में पहला चरण तैयार होकर देश को समर्पित कर दिया गया।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीड़ा) की दूरदृष्टि बनी सफलता की आधारशिला

यदि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस परिवर्तन का इंजन है, तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीड़ा) उसकी मजबूत नींव है।

दो दशक पहले सम्भावनाओं से भरे जेवर और आसपास की को यमुना प्राधिकरण ने पहचाना था। यमुना प्राधिकरण ने यहां भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नियोजित औद्योगिक, आवासीय और संस्थागत विकास की व्यापक योजना तैयार कर ली थी। यह दूरदृष्टि आज वास्तविकता का रूप ले चुकी है।

बेहतर सड़क नेटवर्क, औद्योगिक सेक्टर, निवेश-अनुकूल नीतियां, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सुव्यवस्थित शहरी नियोजन ने इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है।

पहली उड़ान बनी विकास की प्रतीक

पहली वाणिज्यिक उड़ान के साथ सबसे भावुक दृश्य वह रहा, जब इस परियोजना के लिए अपनी भूमि देने वाले किसानों को उसी पहली उड़ान में यात्रा का अवसर मिला। यह केवल सम्मान का क्षण नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक भी था कि विकास की इस यात्रा में किसानों की भागीदारी और योगदान को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया।

यह उड़ान केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली नहीं थी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक यात्रा का प्रतीक बन गई।

औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के साथ ही जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र देश के सबसे बड़े औद्योगिक एवं निवेश केंद्रों में तेजी से विकसित हो रहे हैं।

एयरपोर्ट के आसपास फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब, टॉय पार्क, टेक्सटाइल हब तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाएं आकार ले रही हैं।

एयर कार्गो सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र उत्तर भारत के सबसे बड़े निर्यात और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट और यीड़ा मिलकर इस पूरे क्षेत्र के विकास के दो प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। एक ओर एयरपोर्ट वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहा है, तो दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण उद्योगों, आवासीय परियोजनाओं और आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक भूमि एवं सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

बदलती अर्थव्यवस्था, बदलती तस्वीर

यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक, प्रस्तावित रेल एवं रैपिड रेल कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं ने इस क्षेत्र की रणनीतिक महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप जेवर, दनकौर, रबूपुरा, टप्पल और आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट, उद्योग, रोजगार, व्यापार और सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है। हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव इस क्षेत्र को उत्तर भारत के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।

नई आर्थिक पहचान की उड़ान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी केवल एक एयरपोर्ट बनने की कहानी नहीं है। यह दूरदर्शी योजना, दीर्घकालिक नीति, प्रशासनिक दृढ़ता, किसानों के सहयोग, निवेशकों के विश्वास और आधुनिक आधारभूत संरचना के समन्वित विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जेवर आज यह सिद्ध कर चुका है कि यदि विकास की परिकल्पना दूरदृष्टि, प्रभावी नेतृत्व और समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ की जाए, तो खेतों के बीच बसा एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बन सकता है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने केवल आसमान नहीं छुआ है, बल्कि भारत के औद्योगिक, निवेश और आर्थिक भविष्य की नई उड़ान भी भर दी है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र उत्तर भारत के विकास मॉडल के रूप में स्थापित होगा और वैश्विक निवेश मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराएगा। ■

किसान चौक पर एनसीआर का आधुनिक अंडरपास अपने निर्माण के अंतिम चरण में

जल्द होगा जनता को समर्पित

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक वर्ष के रिकॉर्ड समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित किसान चौक पर दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा और आधुनिक तथा बहुउपयोगी अंडरपास को तैयार करने के करीब पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पूरी कोशिश कर रहा है कि 15 अगस्त से पूर्व इसे जनता को समर्पित कर दिया जाए। 720 मीटर लंबा और लगभग सात लेन चौड़ा यह अंडरपास न केवल गाजियाबाद को गौतमबुद्धनगर से जोड़ेगा बल्कि गाजियाबाद को यमुना एक्सप्रेस-वे तथा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। किसान चौक या गौड़ सिटी सेंटर चौराहे पर बन रहे अंडरपास का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इस चौराहे पर नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के दो हिस्सों से आने वाले यातायात के कारण जाम की भारी समस्या रहती थी। इस समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने यहां अंडरपास बनाने का निर्णय लिया था परंतु इसे साकार किया वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने। उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 130 मीटर रोड पर जगह जगह लगने वाले जाम को समाप्त करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण तथा दूरगामी सुधार कराए हैं।

अप्रैल 2025 में शुरू हुए अंडरपास पर बिसरख की ओर अंतिम स्लैब डाली जा रही है जबकि नीचे अंडरपास का काम लगभग पूरा हो चुका है। अंडरपास के दोनों खुले सिरों को ढंकने के लिए कैनोपी का सामान मेरठ से पहुंचना शुरू हो गया है। अंडरपास निर्माण पर कुल 82 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है जबकि कैनोपी लगाने का खर्च सात करोड़ रुपए अलग है।

इस अंडरपास के चालू हो जाने से दिल्ली मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 से लोग सीधे गौतमबुद्धनगर जिला मुख्यालय, यमुना एक्सप्रेस-वे तथा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंच सकेंगे।

ग्रेटर नोएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक सिविल ए के सिंह क अनुसार इस अंडरपास को जलभराव से मुक्त रखने के लिए दोनों ओर पांच पांच फीट गहरे दो संपवेल बनाए गए हैं जिनमें ढाई फीट पानी भरने पर स्वत: पंप चालू हो जाएंगे। हालांकि कैनोपी से ढंका होने के कारण बारिश का पानी अंडरपास में घुसने की बहुत कम संभावना रहेगी। अंडरपास परियोजना की सतत् निगरानी कर रहे वरिष्ठ प्रबंधक सिविल प्रभात शंकर ने बताया कि यह अंडरपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सबसे चौड़ा अंडरपास होगा। इसकी आने जाने वाली दोनों सड़कें तेरह तेरह मीटर चौड़ी बनाई गई हैं जिनपर एक साथ तीन तीन गाड़ियां आसानी से दौड़ सकेंगी। अंडरपास को जुलाई माह में जनता के उपयोग हेतु खोल देने की संभावना है। ■

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिली नई उड़ान

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 के लिए सज-धज कर तैयार इंडिया एक्सपो मार्ट

लगातार तीन सफल संस्करणों के बाद उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS)-2026 का चौथा अध्याय इस बार नए आत्मविश्वास और वैश्विक संभावनाओं के साथ लिखा जा रहा है। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले इस मेगा आयोजन को अब तक का सबसे भव्य, सुव्यवस्थित और अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापारिक मंच बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, प्राधिकरणों और इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी है।

इस बार की सबसे बड़ी ताकत जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसने इंडिया एक्सपो मार्ट की वैश्विक प्रासंगिकता को कई गुना बढ़ा दिया है। विश्वस्तरीय हवाई संपर्क के कारण अब देश-विदेश के खरीदारों, निवेशकों, प्रदर्शकों और उद्योग प्रतिनिधियों के लिए ग्रेटर नोएडा तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान और तेज होगी। इससे इंडिया एक्सपो मार्ट न केवल उत्तर भारत के सबसे बड़े एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन) केंद्र के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के आर्थिक और व्यापारिक विकास का नया इंजन भी बनेगा।

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल और प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन शशि भूषण लाल सुशील की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठकों में स्पष्ट किया गया है कि यह आयोजन केवल व्यापारिक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कलाओं, स्थानीय उत्पादों और निर्यात क्षमता को वैश्विक मंच प्रदान करने का माध्यम होगा। "वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन (ODOC)" के तहत प्रदेश के ऐतिहासिक और पारंपरिक व्यंजनों को भी अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष राकेश कुमार के अनुसार "UP for Global Growth: Innovation, Manufacturing & Exports" थीम पर आधारित ट्रेड शो में 'मेक इन यूपी', 'एक्सपोर्ट फ्रॉम यूपी', 'ओडीओपी टू ग्लोबल मार्केट्स', 'एमएसएमई एवं स्टार्टअप सशक्तीकरण', 'डिजिटल ट्रेड एंड ई-कॉमर्स' और 'इन्वेस्टमेंट एंड लॉजिस्टिक्स हब' जैसे विषय उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेंगे। सरकार ने इस वर्ष 80 से अधिक देशों के लगभग 550 विदेशी खरीदारों और 45 हजार से अधिक बी2बी खरीदारों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। लगभग 5,000 करोड़ रुपये की बिजनेस इन्क्वायरी, 20,000 करोड़ रुपये की संभावित व्यावसायिक गतिविधियों और 5,000 से अधिक एमओयू हस्ताक्षरित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दरअसल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क, मेट्रो कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय प्रदर्शनी अवसंरचना का संगम अब ग्रेटर नोएडा को वैश्विक व्यापार और निवेश के नए प्रवेशद्वार के रूप में स्थापित कर रहा है। ऐसे में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बनकर उभर रहा है, जो स्थानीय उत्पादों, वैश्विक संपर्क और आधुनिक अवसंरचना के दम पर दुनिया के व्यापारिक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ■

पंचायत 24 हिंन्दी मासिक पत्रिका

के पहले अंक के प्रकाशन पर
हार्दिक शुभकामनाएं

दादरी विधानसभा के प्रमुख विकास कार्य

01. नोएडा प्राधिकरण धनराशि:-492 करोड 04 लाख रुपये।
02. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण धनराशि:- 2952 करोड 19 लाख रुपये।
03. इज्ञा द्वारा वाल्तो नगर धनराशि:- 8 करोड 70 लाख रुपये।
04. पीडब्ल्यूडी0 धनराशि:-164 करोड 53 लाख रुपये।
05. विधानसभा निधि धनराशि:-23 करोड रुपये।
06. शिक्षा क्षेत्र में:- 93 करोड
07. युवाओं के लिये:-20 करोड
08. स्वास्थ्य क्षेत्र में:-175 करोड 36 लाख
09. सिंचाई विभाग क्षेत्र में:- 4 करोड 76 लाख
10. विजली विभाग क्षेत्र में:- 1 करोड 77 लाख
11. जन विकासी योजना के अन्तर्गत दादरी नगर पालिका में:- 4 करोड
12. मुख्यमंत्री राहत कोष से ईलाज हेतु गरीब परिवार को लाभ:-5 करोड

शिक्षा हेतु

1 दादरी विधानसभा में मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा से डिग्री कॉलेज स्वीकृत कराना, विना ऐंटर से मात है, जल्दी भूमि पुजन कर दिया जायेगा	25 करोड
2 दादरी विधानसभा मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा राजकीय आईटी0आई0 कॉलेज स्वीकृत कराना, जिसमें आइगिवा होंगी।	25 करोड
3 मा0 मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल जो कक्षा नर्सरी से कक्षा-12 तक का होगा, जो 35 करोड लागत से बन रहा है जिसमें स्मार्ट कम्प्युटर लैब तथा बच्चों को खेलने के लिये स्टेडियम व व्यायाम भी बनेगा	35 करोड
4 दादरी में राजकीय इण्टर कॉलेज बनवाया	5.5 करोड
5 मिहिर भोज इण्टर कॉलेज, दादरी में बने सभी का निर्माण कार्य चल रहा है इसी शीघ्र ही विधानसभा दादरी के अन्य बोर्ड स्कूलों में कार्य हा रहा है।	1.20 करोड
6 मिहिर भोज पी0जी0 कॉलेज में विज्ञान की लैबों का निर्माण कराया	60 लाख
7 दादरी में युवाओं के कल्याणिता की तैयारी के लिए सीएसआरफ द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी की कराया कार्य तथा इसके उपर शिल्पिका बनवाने के लिये भी करोड रुपये स्वीकृत कराये है	2 करोड 80 लाख

युवाओं के लिये

1 बेरोजगार साथियों के लिए 2021 में आने वाले कम्पनियों में 40 प्रतिशत स्थानीय वासों का आरक्षण कोटा की आवश्यकता रूप से स्वीकृत कराई	20 करोड
2 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा से बिटटेस में स्टेडियम बनने का कार्य जल्दी से भूमि पुजन होगा	
3 दादरी में मा0 मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में नवीन नि:शुल्क कोचिंग सैंटर स्वीकृत कराना जोकि सत्र 2026-27 में शुरू हो जायेगा	

पी०डब्ल्यू०डी० महत्वपूर्ण सडक

1 दादरी-बिसाख, रुथवली, सधुपुर, एल0टी0पी0भी0, उंचागांव से स्वंसेडा, आवरा सम्भाला रोड तक सडक का चौडीकरण व सुदृढीकरण कार्य।	17 करोड
2 जीटी0 रोड सैतली चौकी से नोगला मसार, सैतली ग्रामाला, छपारा, को सडक का चौडीकरण व सुदृढीकरण जी कलौंदा जाना सेड तक	12 करोड
3 उपसील-मौहपुर मार्ग खुत समय से क्षतिग्रस्त है, उसका चौडीकरण व सुदृढीकरण	6 करोड
4 जीटी0 रोड वालऊपुर लाल से वालऊपुर इखाला कस्दर वाला इन्दालापुर तिरोडी तक चौडीकरण व सुदृढीकरण	11 करोड
5 ग्राम खेडी से खोटना खटी0आपुर तिलपता मन्डौडा जुनवात तक ग्रेटर नोएडा तक चौडीकरण व सुदृढीकरण	22 करोड
6 ग्राम वारसिर से आजमपुर से जीटी0 रोड से तक की पटी सकरीनपुर कैमराला से तेले हुए आजमपुर स्टेशन तक चौडीकरण व सुदृढीकरण	11 करोड
7 ग्राम पहलपुर नई बस्ती से जीटीलीड सें बील से मामाडा में आजमपुर स्टेशन तक चौडीकरण व सुदृढीकरण	9 करोड
8 जीटी0 रोड भगत पटनां से बिटटेस से आरवीआरडीपिड तक चौडीकरण व सुदृढीकरण व दोनों तरफ नाले व नलि में डिवाईडर, खम्बे को शिफ्टिंग का कार्य	35 करोड
9 अन्य चौडीकरण व सुदृढीकरण के कार्य	33 करोड

पी०डब्ल्यू०डी० पुल

1 खटाला में पुल	4 करोड	4 रबेड़ी में दो पुल	4 करोड
2 ककौडा में पुल	25 लाख	5 बील में पुल	1 करोड
3 प्यावली में पुल	18 लाख		

स्वास्थ्य क्षेत्र में

1 दादरी विधानसभा में मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा से 100 शैय्यायुक्त अस्पताल का निर्माण, दादरी कलों में शुरू किया, जिसमें 36 डॉक्टर डॉक्टर स्टॉफ, हर बीमारी का ईलाज होगा, आमजन को दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा	100 करोड
2 दादरी विधानसभा में 50 शैय्या युक्त अस्पताल जिसकी स्वीकृति हो गई टेंडर की प्रक्रिया में है, जिसका लाभ आमजन को बहुत होगा	35 करोड
3 ग्राम खटाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्डिंग का निर्माण कार्य और खटाली और सेमीडिकल स्टोक के पास सतीश में नहीं है	5.5 करोड
4 बिसरख ग्रेटर नोएडा सैटर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य में विकसित कराया, जिसमें इमरजेन्सी और पैरामैडिकल स्टॉफ की बढोत्री हुई आमजन को लाभ होगा	20 करोड
5 मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न गरीब परिवारों को ईलाज हेतु सहायता दिलाई	5 करोड
6 इन पेटर राज्य दवाई निर्माण कार्य	9 करोड 86 लाख

सिचाई विभाग द्वारा

1 ग्राम सैहली नहर की पटरी पर सडक निर्माण (मिकलावास; उलाठे पर	1करोड
2 ग्राम सुरीबपुरा नहर की पटरी पर जावरा राजवाहे पर सडक निर्माण डविफ0गी0	2 करोड 40 लाख
3 बिसरख में राजवाह सडक निर्माण	
4 द्वाबरा कोठी पर कार्य	1करोड

सिचाई विभाग से पुल

कैमराला में पुल	22 लाख
कैलाशपुर में पुल	14 लाख

बिजली हेतु

1 दुरियाई में बिजली घर का निर्माण 24 लाख 3 बालऊपुर में बिजली घर का निर्माण 24 लाख
2 सैंताली में बिजली घर का निर्माण 24 लाख 4 ग्राम सुनीवाह में बिजली घर का निर्माण कार्य 20 लाख
5 ग्राम डोडलापुर पालवरी में बिजली घर का निर्माण कार्य 20 लाख
6 दादरी विधानसभा में पुराने तारों को स्थान पर एलीबीकेबिल का कार्य विद्युत विभाग से 50 लाख
7 दादरी के 33/11 केवी0 उपकेन्द्र बिसरीन में 11 केवी0 शामिल भारत सिंह-मार्ग कोठी को कोकिंग को समाप्त कराने का कार्य। 15 लाख का कार्य
8 दादरी बिजलीघर व बिटटेस बिजलीघर 5 MBA के ट्रांसफार्मर 2 करोड

तेजपाल नागर
विधायक, दादरी

नोएडा के श्रमिक आंदोलन में हिंसा का विस्फोट और अर्बन नक्सल का सवाल

15 अप्रैल, 2026 देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में दर्ज हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा कि भारत में अब कोई भी जिला नक्सल हिंसा प्रभावित श्रेणी में नहीं बचा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लंबे समय से यह घोषणा करते रहे थे कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत नक्सल हिंसा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, इसी दौर में देश की आर्थिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में श्रमिक आंदोलन हिंसक हो उठा। आगजनी, पथराव, तोड़फोड़, पुलिस वाहनों को जलाना, 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को नुकसान, 40 से 45 हजार लोगों की भीड़, कथित विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया हैंडल और कुछ संगठनों की भूमिका की जांच—इन सबने कुछ नए प्रश्न खडे कर दिए हैं। क्या यह केवल वेतन वृद्धि का आंदोलन था? क्या इसके पीछे संगठित वैचारिक हस्तक्षेप की कोई परत भी थी? क्या जंगलों में सिमटता नक्सलवाद शहरों में नया रूप तलाश रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या नोएडा अर्बन नक्सल गतिविधियों के लिए नया ठिकाना बनता जा रहा है?

श्रमिक आंदोलन के लिए आखिर नोएडा ही क्यों?

यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल, नोएडा देश के सबसे बड़े औद्योगिक, निवेश और रोजगार केंद्रों में शामिल है। यहां लगभग 30 हजार औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं।करीब 12 लाख प्रत्यक्ष श्रमिक उद्योगों में कार्यरत हैं।

एमएसएमई और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित लगभग 18 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों की बड़ी आबादी रहती है और तेजी से बढ़ता शहरीकरण, सामाजिक असमानता और आर्थिक दबाव मौजूद हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञ वर्षों से मानते रहे हैं कि जहां बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक, आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष मौजूद होता है, वहां कट्टर वैचारिक समूहों के लिए जनाधार बनाने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि नोएडा केवल एक औद्योगिक शहर नहीं, बल्कि विचारधारात्मक प्रभाव और जन-संगठन निर्माण के लिए भी अत्यंत संवेदनशील भूगोल माना जा सकता है।

श्रमिकों का असंतोष वास्तविक था?

यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि श्रमिकों की शिकायतें वास्तविक थीं। हरियाणा में न्यूनतम वेतन में लगभग 35 प्रतिशत वृद्धि के बाद नोएडा के श्रमिक स्वयं को वेतन असमानता का शिकार महसूस कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगें थीं— समान और न्यायसंगत वेतन, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, समय पर वेतन, वेतन पर्ची, साप्ताहिक अवकाश, सुरक्षित कार्यस्थल, मनमानी कटौती पर रोक, बिना कारण नौकरी से निकाले जाने पर रोक और बढ़ती महंगाई, मकान किराया, बिजली, गैस और राशन की कीमतों ने असंतोष को और गहरा किया। इसलिए आंदोलन की जड़ें आर्थिक थीं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तविक आर्थिक असंतोष को कुछ तत्वों ने अपने वैचारिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया?

जांच में सामने आए नए आयाम

पुलिस जांच में कुछ गंभीर पहलू सामने आए—17 व्हाट्सएप समूहों की पहचान। कुछ संगठनों की सक्रिय भूमिका। कथित रूप से विदेशों से एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त होने की जांच। पाकिस्तान से संचालित बताए गए दो सोशल मीडिया हैंडल। कई बैठकों और समन्वित गतिविधियों के आरोप।

एनएसए के तहत कार्रवाई। एसआईटी द्वारा डेढ़ हजार पन्नों की रिपोर्ट । पुलिस का दावा है कि हिंसा स्वतःस्फूर्त नहीं थी, बल्कि कुछ तत्वों ने उसे दिशा देने का प्रयास किया।

हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों के बाद ही मानी जाएगी।

अर्बन नक्सल: एक अवधारणा, एक बहस

"अर्बन नक्सल" कोई विधिक श्रेणी नहीं, बल्कि सुरक्षा

विमर्श में प्रयुक्त एक अवधारणा है। इसका आशय उन शहरी नेटवर्कों से लगाया जाता है जिन पर आरोप लगाया जाता है कि वे असंतोष, आंदोलन, वैचारिक अभियान, डिजिटल माध्यम और संगठनों के जरिए राज्य-विरोधी गतिविधियों के लिए आधार तैयार करते

हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना रहा है कि जब जंगलों में सशस्त्र नक्सलवाद कमजोर पड़ता है, तब उसकी विचारधारा शहरों में नए सामाजिक प्रश्नों के सहारे अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास कर सकती है।

इसी संदर्भ में नोएडा की घटना ने बहस को जन्म दिया है।

क्या यह कोई वैचारिक संदेश था?

15 अप्रैल को देश को नक्सल हिंसा से मुक्त घोषित किया गया। 13 अप्रैल को नोएडा हिंसा हुई। समय का यह संयोग कई प्रश्न पैदा करता है— क्या यह केवल संयोग था? क्या किसी ने औद्योगिक असंतोष को प्रतीकात्मक प्रतिरोध में बदलने का प्रयास किया?

क्या देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में अस्थिरता पैदा कर कोई राजनीतिक या वैचारिक संदेश देने की कोशिश की गई? क्या "वर्ग संघर्ष" की पुरानी अवधारणाओं को नए शहरी संदर्भ में पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ?

हालांकि इन प्रश्नों के उत्तर अभी जांच और समय के गर्भ में हैं।

सबसे बड़ी चिंता: नोएडा ब्रांड पर हमला

नोएडा केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी और शो विंडो है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हजारों औद्योगिक इकाईयां और लाखों श्रमिक यहां है।

कई बड़ी भविष्य की अहम परियोजनाएं भी यहां प्रस्तावित हैं। दिल्ली के करीब होने के कारण यहां घटी घटना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। वहीं इन घटनाओं का उत्तर प्रदेश की छवि पर भी असर पड़ता है। ऐसे समय में व्यापक हिंसा निवेशकों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। यदि किसी भी प्रकार की संगठित हिंसा औद्योगिक वातावरण को प्रभावित करती है, तो उसका असर केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय निवेश परिदृश्य पर पड़ता है।

सरकार और प्रशासन के सामने तीन बड़ी चुनौतियां

पहली चुनौती : श्रमिक न्याय अर्थात न्यायसंगत वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों का कड़ाई से अनुपालन।

दूसरी चुनौती : औद्योगिक स्थिरता अर्थात उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन को बनाए रखना।

तीसरी चुनौती : आंतरिक सुरक्षा अर्थात वास्तविक श्रमिक असंतोष और कथित वैचारिक या बाहरी हस्तक्षेप के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना।

निष्कर्ष: जंगल से शहर तक की बदलती चुनौती

भारत में पारंपरिक नक्सल हिंसा का क्षरण निस्संदेह राष्ट्रीय उपलब्धि है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती हैं।

नोएडा की घटना ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है—आर्थिक असंतोष, डिजिटल दुष्प्रचार, वैचारिक नेटवर्क, सोशल मीडिया और बड़े शहरी श्रमिक समूहों का मिश्रण भविष्य की नई चुनौतियां पैदा कर सकता है।

हालांकि अभी यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि नोएडा की हिंसा का सीधा संबंध किसी संगठित अर्बन नक्सल साजिश से था। इसका अंतिम उत्तर जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रियाओं से ही निकलेगा। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि इस घटना ने देश को आगाह अवश्य किया है कि जंगलों में कमजोर पड़ती उग्र विचारधाराएं यदि नए ठिकाने तलाशती हैं, तो उनके लिए भारत के तेजी से बदलते औद्योगिक शहर अगली प्रयोगशाला बन सकते हैं। इसलिए नोएडा की घटना केवल एक श्रमिक आंदोलन नहीं, बल्कि श्रम, विकास, लोकतांत्रिक असंतोष और राष्ट्रीय सुरक्षा—इन चारों के चौराहे पर खड़ा एक ऐसा प्रकरण है, जिसने भारत के सामने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है— **क्या देश नक्सलवाद के अंत का उत्सव मना रहा है, या उसके नए शहरी रूप को पहचानने की शुरुआत कर रहा है?** ■

दावेदारी दादरी विधानसभा की 2027 में भाजपा के गढ़ में टिकट की जंग, विपक्ष के लिए बेहतर विकल्प कौन?

दिल्ली-एनसीआर का राजनीतिक भूगोल केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला आज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर के तीव्र विकास ने जिले को राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर विशिष्ट स्थान दिलाया है। राजनीतिक दृष्टि से यह जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां की तीनों विधानसभा सीटें—नोएडा, दादरी और जेवर—पिछले लगभग एक दशक से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं।

केवल विधानसभा ही नहीं, बल्कि जिले की लगभग पूरी राजनीतिक संरचना पर भाजपा का प्रभाव है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से डॉ. महेश शर्मा लगातार तीसरी बार सांसद हैं, राजयसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा तथा नरेंद्र सिंह भाटी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी भाजपा से हैं। जिले की एकमात्र नगर पालिका दादरी की अध्यक्ष गीता पंडित भी भाजपा की ही प्रतिनिधि हैं।

ऐसे में जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के भीतर टिकट दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। लेकिन तीनों सीटों में सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है—दादरी विधानसभा सीट।

क्यों महत्वपूर्ण है दादरी?

दादरी विधानसभा को केवल एक विधानसभा सीट मानना भूल होगी। यह सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई आयामों का प्रतिनिधित्व करती है। यहां गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, वहीं बड़ी संख्या में शहरी मतदाता भी मौजूद हैं, जिन्हें भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। यही कारण है कि यहां जातीय समीकरण, विकास, संगठन और व्यक्तित्व—चारों तत्व चुनावी परिणाम तय करते हैं।

भाजपा

क्या तीसरी बार भी तेजपाल नागर का ही नंबर?

भाजपा की ओर से सबसे बड़ा और स्वाभाविक नाम है—वर्तमान विधायक मास्टर तेजपाल सिंह नागर।

लगातार दो बार विधायक चुने गए तेजपाल नागर ने पिछली बार पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाले नेताओं में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उनकी यह उपलब्धि इसलिए और बड़ी मानी जाती है क्योंकि चुनाव से पहले उनके खिलाफ अपनी ही जाति का भारी विरोध और एंटी-इनकंबेंसी की चर्चा जोरों पर थी। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान था कि वह या तो चुनाव हार सकते हैं या बेहद कम अंतर से जीतेंगे, लेकिन परिणाम इसके ठीक विपरीत आए।

क्षेत्र में सड़कों, संपर्क मार्गों और सभी क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्यों के कारण उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। अपने विकास कार्यों को ही वह अपनी मज़बूत दावेदारी का आधार भी मानते है। हालांकि, लगातार दो कार्यकाल के बाद स्वाभाविक एंटी-इनकंबेंसी स्वभाविक है। राजनीति का यह शाश्वत सत्य है कि जनप्रतिनिधि से अपेक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती और हर अपेक्षा की पूर्ति संभव नहीं होती।

फिलहाल भाजपा के भीतर टिकट की दौड़ में मास्टर तेजपाल सिंह नागर अभी भी सबसे प्रबल दावेदार दिखाई देते हैं।

आशीष भाटी : विरासत से मिले अनुभव और युवा ऊर्जा के बल पर सफलता पाने का दम

दूसरा बड़ा नाम है भाजपा एमएलसी और गुर्जर समाज के प्रभावशाली नेता नरेंद्र सिंह भाटी के पुत्र एडवोकेट आशीष भाटी का।

आशीष भाटी की तेजी से बढ़ती राजनीतिक

सक्रियता ने दावेदारों की सूची में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है और उन्होंने बचपन से चुनावी रणनीति और संगठन को करीब से देखा है। ऐसे में व्यवहारिकता और राजनीति की समझ उनमें है.

एक युवा चेहरे के रूप में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। पिता नरेंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक अनुभव और मजबूत सामाजिक आधार उनके लिए अतिरिक्त राजनीतिक पूंजी साबित हो सकता है। इसके बावजूद उन्होने स्वयं को जमीन से जोड़कर रखा है। पिता की विरासत जहां उन्हें समाज में तीव्र स्वीकार्यता दिलवा रही है वहींए युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता उनका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सूत्रों की माने तो भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच अशीष भाटी की उपस्थिति और सक्रियता की चर्चा है।

हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्होंने अभी तक स्वयं कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में उनकी लोकप्रियता का वास्तविक चुनावी परीक्षण अभी बाकी है। फिर भी इस युवा ने तेजी से पार्टी नेतृत्व और राजनीतिक पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

देव भाटी : संगठन का सिपाही और युवाओं की पसंद

भाजपा की संभावित सूची में एक और तेजी से उभरता नाम है जिला पंचायत सदस्य देव भाटी का

देवा भाटी

है।

देव भाटी का राजनीतिक सफर पारंपरिक राजनीतिक परिवार से नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है। जिस उम्र में कोई युवा मौज मस्ती में डूबा होता है उस अल्हड़ उम्र में उन्होंने राजनीति और संगठन की बारीकीयां सीखा ली थी। छोटी उम्र में बड़ी राजनीतिक छलांग लगाने वाले नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। उनका सौम्य और शालीन स्वभाव भी लोगों को प्रभावित करता है।

वह सांसद डॉ. महेश शर्मा को अपना राजनीतिक अभिभावक बताते हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को संगठन में सकारात्मक रूप से देखा जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जातीय दबाव के बावजूद पार्टी लाइन पर खड़े रहने की उनकी छवि ने उन्हें संगठन के विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया। बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं में उनकी लोकप्रियता और सरल स्वभाव उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है।

सत्येंद्र अवाना : दादरी की ओर क्यों?

सतेंद्र अवाना

दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति शुरू करने वाले सतेंद्र अवना का नाम भाजपा के संभावित दावेदारों की सूची में शामिल है।

मूलतः नोएडा क्षेत्र से आने वाले अवाना ने दादरी विधानसभा की ओर राजनीतिक रुख किया है।इसके पीछे राजनीतिक गणित स्पष्ट है। नोएडा सीट पर पंकज सिंह की मजबूत स्थिति और उनके पिता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राजनीतिक प्रतिष्ठा को देखते हुए वहां टिकट की संभावनाएं सीमित हैं।

जेवर सीट पर जातीय समीकरणों की अपनी जटिलताएं हैं। ऐसे में दादरी उनके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है। हलाकि उन्हे गुर्जर दावेदार होने के बावजूद गुर्जर समाज के भाटी और नागर मतदाताओं बीच अपने लिए जगह बनाना और स्वीकारोक्ति एक चुनौती है।

बिजेंद्र भाटी 'प्रमुख'

बिजेंद्र भाटी प्रमुख : चिटेहरा गांव निवासी बिजेंद्र सिंह भाटी वर्तमान में दादरी ब्लॉक प्रमुख है। वह जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं. वह भी टिकट के दावेदारों की सूची में शामिल हैं।

ऐसे नाम जो बदल सकते है समीकरण :

कुछ अन्य नाम भी राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा में है जो चौकाने वाले हैं। इनमें एक नाम

सुरेंद्र सिंह नागर

वर्तमान राजयसभा सांसद **सुरेंद्र सिंह नागर** का है। लेकिन सवाल यह इठता है क्या सुरेंद्र सिंह नागर केंद्र की राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आना कहते है? इस बारे में राजनीतिक जानकारी का मानना है कि यदि विधानसभा पहुंचने के बाद सुरेंद्र सिंह नगर को पार्टी बड़ी भूमिका सौंपती है (यदि चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर उप-मुख्यमंत्री या कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है) तो ऐसा संभव हो सकता है।

प्रणीत भाटी : वही एक अन्य नाम प्रणीत भाटी का भी सामने आ रहा है। प्रणीत भाटी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैंऔर उनके परिवार की पृष्ठभूमि तथा पार्टी के प्रति समर्पण किसी भी अन्य कार्यकर्ता की अपेक्षा अलग स्तर का है। वह पिछले काफी समय से पार्टी के लिए राजनीतिक मुख्य धारा मैं बड़ी भूमिका के लिए प्रयास कर रहे हैं।

क्या भाजपा महिला कार्ड खेल सकती है?

सामान्य परिस्थितियों में भाजपा गौतम बुद्ध नगर की किसी सीट पर महिला प्रत्याशी उतारती नहीं दिख रही, लेकिन संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण के समर्थन के बाद राजनीतिक संदेश देने के लिए पार्टी किसी सीट पर महिला उम्मीदवार उतारने का जोखिम उठा सकती है। यदि ऐसा होता है तो दादरी से कुछ प्रमुख नाम उभर सकते हैं।

गीता पंडित

गीता पंडित तीन बार नगर पालिका परिषद की चेयरमैन बनी है। दादरी नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष गीता पंडित पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं रही हैं। उनका राजनीति में प्रवेश परिस्थितिवश हुआ है, लेकिन उन्होंने व्यवहार, कार्यशैली और विकास कार्यों के माध्यम से अलग पहचान बनाई है। नगर पालिका में उनके कार्यों की चर्चा उनके राजनीतिक कद को बढ़ाती है। उनके साथ कोई विवाद भी नहीं जुड़ा है।

महामेधा नागर

इस कड़ी में दूसरा नाम महामेधा नागर का है। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत कर भाजपा युवा मोर्चा और पार्टी संगठन की जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। वर्तमान में भाजपा पार्टी की प्रदेश मंत्री है। यदि पार्टी महिला के उम्मीदवार के साथ जातीय समीकरण साधती है तो महामेधा नागर पार्टी की पसंद हो सकती हैं।

कुशल सिंह

दादरी विधानसभा सीट पर महिला उम्मीदवार के तौर पर कुशल सिंह का नाम भी हाल ही में सामने आया है। उनके पति रविंद्र तौगड़ ने पिछले विधानसभा चुनावों में दादरी विधानसभा सीट पर भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश की थी। कुशल सिंह शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय हैं और कौशल्या वर्ल्ड स्कूल समूह का संचालन करती हैं। उनका अपना राजनीतिक आधार नहीं है। उनके पति ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। चूंकि राजनीति अनिश्चिताओं का खेल है। ऐसे में यदि कुछ उलटफेर हुआ तो कुशल सिंह भी एक महिला के रूप में भाजपा से उम्मीदवार हो सकती है।

शालिनी सिंह

शालिनी सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। उनके पिता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, भाई करण भूषण सिंह सांसद और प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं। वहीं उनका ससुराल भी बिहार के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में है। संघ से उनके पुराने जुड़ाव और प्रशिक्षण को भी उनकी राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाता है। वह लेखिका, कवयित्री, शिक्षाविद, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान रखती हैं। पिछले कुछ समय से वह गौतम बुद्ध नगर, विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो कि दादरी विधानसभा का हिस्सा है, में काफी सक्रिय है जिससे उनकी दावेदारी की चर्चाओं को बल मिलता है।

समाजवादी पार्टी : क्या दादरी में वापसी की तैयारी?

दादरी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार पर ध्यान दिया है।

राजकुमार भाटी

पार्टी प्रवक्ता और पूर्व प्रत्याशी राजकुमार भाटी अभी भी सबसे चर्चित नाम हैं। गुर्जर समाज और विशेषकर युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है।हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि वह स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की शैली को देखते हुए अंतिम समय में भी उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

डॉ. महेंद्र सिंह नागर

लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरुद्ध लगभग तीन लाख मत प्राप्त करने वाले डॉ. महेंद्र सिंह नगर आज सपा के सबसे स्वीकार्य चेहरों में गिने जाते हैं।

उनका सौम्य स्वभाव, अखिलेश यादव से निकटता और व्यापक सामाजिक संपर्क उन्हें मजबूत दावेदार बनाते हैं।

इंद्र प्रधान

पूर्व जिलाध्यक्ष और जुझारू नेता इंद्र प्रधान ने अपनी दावेदारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की है। दादरी रैली की सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि सपा युवा और संगठन आधारित चेहरे पर दांव खेलती है तो उनका नाम गंभीरता से लिया जाएगा।

सुधीर भाटी

वर्तमान जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी के परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि और अखिलेश यादव से निकटता उनकी ताकत है। पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव का उनके आवास पर जाना भी राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

फकीरचंद नगर

पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष फकीरचंद नगर भी मजबूत सामाजिक आधार के कारण दावेदारों की सूची में शामिल हैं।

कांग्रेस : दीपक भाटी 'चोटीवाला' की एकल लड़ाई

कांग्रेस में फिलहाल दादरी से सबसे प्रमुख और लगभग एकमात्र सक्रिय चेहरा दीपक भाटी 'चोटीवाला' का दिखाई देता है। वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं और जिले में संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की समस्या हमेशा से पैराशूट उम्मीदवारों की रही है। यदि पार्टी इस बार स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है तो दादरी से दीपक भाटी का नाम लगभग तय माना जा सकता है।

बसपा : सन्नाटा, लेकिन राजनीति में शून्य कभी स्थायी नहीं होता

एक समय था जब गौतम बुद्ध नगर की दोनों विधानसभा सीटें—दादरी और जेवर और एकमात्र गौतमबुद्धनगर लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में थीं। मायावती का गृह जनपद होने और प्रदेश में बसपा की लहर के कारण पार्टी को यहां भारी समर्थन मिला। लेकिन वर्तमान में बसपा संगठनात्मक रूप से कमजोर दिखाई दे रही है और अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है।

फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि बसपा को कभी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। यदि पार्टी कोई मजबूत सामाजिक समीकरण साधने वाला उम्मीदवार उतारती है तो वह मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है।

दादरी केवल एक सीट नहीं, 2027 की राजनीतिक प्रयोगशाला

दादरी विधानसभा चुनाव-2027 में कई परतें एक साथ मौजूद हैं—भाजपा की सत्ता विरोधी लहर की चुनौती, विकास बनाम सामाजिक समीकरण, युवा नेतृत्व की मांग, महिला प्रतिनिधित्व की संभावना और विपक्ष की पुनर्सक्रियता।

आज की स्थिति में भाजपा बढ़त में दिखाई देती है, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां स्थिर नहीं रहतीं। टिकट वितरण, जातीय समीकरण, विपक्षी एकजुटता और चुनावी हवा अगले कुछ महीनों में पूरी तस्वीर बदल सकते हैं।

एक बात निश्चित है—गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों में यदि कोई विधानसभा 2027 में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोमांच, सबसे ज्यादा अटकलें और सबसे ज्यादा रणनीतिक दिलचस्पी पैदा करने वाली है, तो वह दादरी विधानसभा ही है। ■

आखिरकार नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मिल ही गया नया प्रशासनिक मुख्यालय

करीब एक दशक के लंबे इंतजार, कई बार बदली समय-सीमाओं, तकनीकी परीक्षणों और प्रशासनिक औपचारिकताओं के बाद आखिरकार नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) को उसका नया आधुनिक प्रशासनिक मुख्यालय मिल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर-96 स्थित लगभग 390.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण कर इसे जनता और प्रशासन को समर्पित किया।

वर्ष 1976 में स्थापित नोएडा प्राधिकरण का सेक्टर-6 स्थित पुराना कार्यालय बढ़ती आबादी, विस्तारित प्रशासनिक दायित्वों और सीमित संसाधनों के कारण अपनी उपयोगिता खोने लगा था। मुख्य कार्यालय, जल विभाग और उद्यान विभाग अलग-अलग स्थानों से संचालित होने के कारण नागरिकों को एक ही कार्य के लिए कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नया मुख्यालय इस समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत करता है। अब अधिकांश प्रमुख विभाग एक ही परिसर में कार्य करेंगे, जिससे जनसुनवाई, शिकायत निवारण, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनेगी।

करीब 24 हजार वर्गमीटर (लगभग छह एकड़) क्षेत्रफल में विकसित यह आधुनिक ग्रीन कैंपस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परिसर में दो आधुनिक टावर, दो बेसमेंट, विशाल ऑडिटोरियम, बोर्ड रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, जनसुनवाई केंद्र तथा 11 हाई-स्पीड लिफ्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भवन का डिजाइन ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

परियोजना की मूल स्वीकृत लागत 478 करोड़ रुपये थी, जिसे पुनरीक्षण के बाद

घटाकर 390.06 करोड़ रुपये किया गया। निर्माण के दौरान संरचनात्मक मजबूती को लेकर उठे प्रश्नों के बाद विशेषज्ञों की सलाह पर सुरक्षा ऑडिट कराया गया। आईआईटी-दिल्ली की अनुशंसाओं के अनुरूप आवश्यक तकनीकी सुधार किए गए, जिसके बाद भवन को सुरक्षित एवं संचालन योग्य घोषित किया गया।

यह भवन केवल एक नया कार्यालय नहीं, बल्कि नोएडा के प्रशासनिक आधुनिकीकरण, बेहतर नागरिक सेवाओं और भविष्य की स्मार्ट शहरी शासन व्यवस्था का नया प्रतीक है।

परियोजना एक नजर में

परियोजना प्रारंभ: 05 जनवरी 2016

कार्य पूर्ण: 01 अप्रैल 2026

लोकार्पण: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा

कुल स्वीकृत परियोजना लागत: 478.00 करोड़ रुपये

पुनरीक्षित स्वीकृत लागत: 390.06 करोड़ रुपये

स्वीकृत सिविल कार्य लागत: 255.58 करोड़ रुपये

पुनरीक्षित सिविल कार्य लागत: 295.00 करोड़ रुपये

स्वीकृत अनुबंध राशि: 251.12 करोड़ रुपये

सिविल कार्य पर कुल भुगतान: 266.05 करोड़ रुपये

भवन का स्वरूप

भूखंड क्षेत्रफल: 24,000 वर्गमीटर

प्रस्तावित एफएआर: 58,926 वर्गमीटर

दो बेसमेंट का कुल क्षेत्रफल: 39,356 वर्गमीटर

टावर-1 क्षेत्रफल: 40,824 वर्गमीटर

टावर-2 क्षेत्रफल: 14,840 वर्गमीटर

ऑडिटोरियम: 1,780 वर्गमीटर

नए मुख्यालय की प्रमुख विशेषताएं

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी।

पर्यावरण अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष (ग्रीन बिल्डिंग) डिजाइन।

दो आधुनिक टावर और दो विशाल बेसमेंट।

11 हाई-स्पीड लिफ्ट, अत्याधुनिक बोर्ड रूम एवं कॉन्फ्रेंस हॉल।

विशाल ऑडिटोरियम और आधुनिक जनसुनवाई केंद्र।

पर्याप्त पार्किंग एवं नागरिक सुविधाएं।

अधिकांश विभाग एक ही परिसर में संचालित होने से 'सिंगल विंडो व्यवस्था'।

मंजिलवार विभागीय व्यवस्था

भूतल (ग्राउंड फ्लोर)

स्वागत कक्ष

सभागार

औद्योगिक विभाग

संस्थागत विभाग

वाणिज्यिक विभाग

विधि विभाग

प्रथम तल

जन सुनवाई केंद्र

आवासीय भवन विभाग

ग्रुप हाउसिंग विभाग

द्वितीय तल

आवासीय भूखंड विभाग

भूलेख विभाग

आईजीआरएस

आरटीआई विभाग

तृतीय तल

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्मिक विभाग

वित्त विभाग

चतुर्थ तल

नियोजन विभाग एवं भवन प्रकोष्ठ विभाग

पंचम तल

एसीईओ (ACEO) का कार्यालय

मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय

महाप्रबंधक (सिविल एवं जल) का कार्यालय

उद्यान निदेशक का कार्यालय

उपमहाप्रबंधक (सिविल, जल, इंडस्ट्रियल एवं जनस्वास्थ्य) का कार्यालय

षष्ठम तल

सीईओ (CEO) का कार्यालय

एसीईओ (ACEO) का कार्यालय

सप्तम तल

प्राधिकरण अध्यक्ष (चेयरमैन) का कार्यालय

बोर्ड रूम

एक दशक का इंतजार आखिर हुआ खत्म

यह परियोजना केवल एक भवन निर्माण तक सीमित नहीं रही। निर्माण के दौरान तकनीकी जांच, लागत पुनरीक्षण, सुरक्षा ऑडिट और कई बार टलती उद्घाटन तिथियों ने इसे लंबे समय तक चर्चा में बनाए रखा। एक समय ऐसा भी था जब भवन लगभग तैयार होने के बावजूद उद्घाटन की अंतिम तिथि तय नहीं हो पा रही थी। अब मुख्यमंत्री द्वारा इसके लोकार्पण के साथ वह लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। सेक्टर-96 का यह नया प्रशासनिक परिसर आने वाले वर्षों में नोएडा के सुशासन, त्वरित नागरिक सेवाओं और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का नया केंद्र बनेगा। ■

शिक्षा का अधिकार या निजी स्कूलों की मनमानी?
प्रशासन के आदेश की अनदेखी

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और वंचित बच्चों के लिए कितने अवसर पैदा करता है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) इसी सोच की उपज है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों के द्वार खोलने का प्रयास किया। लेकिन गौतमबुद्धनगर की हालिया घटनाएं यह सवाल उठाने को विवश करती हैं कि क्या कुछ निजी विद्यालय इस संवैधानिक भावना को केवल एक औपचारिकता मानते हैं?

क्या वे स्वयं को शासन, प्रशासन और कानून से भी ऊपर समझने लगे हैं? जनपद में आरटीई के तहत चयनित 950 से अधिक बच्चे अब भी अपने दाखिले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये केवल आंकड़े नहीं हैं; ये उन परिवारों की उम्मीदें हैं, जिनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सपना है और आरटीई उस सपने तक पहुंचने का एकमात्र पुल। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी लगातार निजी विद्यालयों से अपील कर रहे हैं कि पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। बैठकें आयोजित हो रही हैं, निर्देश जारी किए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग पोर्टल पर प्रविष्टियां अपडेट करने की बात कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जनपद के कई प्रतिष्ठित विद्यालयों का रवैया प्रश्नों के घेरे में है। स्थिति की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में 32 में से 15 विद्यालयों ने भाग लेना ही उचित नहीं समझा। इनमें बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर-122, द मिलेनियम स्कूल सेक्टर-119, राघव ग्लोबल स्कूल, रामाज्ञा स्कूल सेक्टर-50 एवं दादरी, संस्कार रोजाजलालपुर, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क-5, सेंट मैरी स्कूल नॉलेज पार्क-5, प्रेजिडियम स्कूल, केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल, रामाज्ञा स्कूल सेक्टर डेल्टा, इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल तथा ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल पिपलका जैसे नाम शामिल हैं।

इन विद्यालयों की अनुपस्थिति केवल एक बैठक से दूरी नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक उत्तरदायित्व से दूरी भी प्रतीत होती है, जिसे शिक्षा संस्थानों की आत्मा माना जाता है।

निस्संदेह, कुछ विद्यालयों ने अपात्र बच्चों के चयन और प्रमाणपत्रों में त्रुटियों की बात उठाई है। यदि ऐसी शिकायतें हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इस बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जांच और प्रक्रियाओं की आड़ में सैकड़ों बच्चों के भविष्य को अनिश्चितता में छोड़ दिया जा सकता है? प्रशासन का रुख स्पष्ट है। शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने वाले विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि अनावश्यक विलंब, आनाकानी अथवा निर्देशों की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नोटिस और आवश्यकता पड़ने पर मान्यता निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। यह केवल प्रशासनिक चेतावनी नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि शिक्षा का अधिकार किसी की कृपा नहीं, बल्कि कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।

दरअसल, यह पूरा प्रकरण एक बड़े सामाजिक द्वंद्व को सामने लाता है। एक ओर सरकार और प्रशासन शिक्षा में समान अवसर की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निजी विद्यालयों का व्यवहार यह संकेत देता है कि वे सामाजिक दायित्व से अधिक अपनी संस्थागत सुविधाओं और प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं। यदि प्रतिष्ठित विद्यालय आरटीई को बोझ समझने लगें, तो फिर शिक्षा में समानता और समावेश का सपना कैसे साकार होगा? विद्यालयों की ऊंची इमारतें, आधुनिक परिसर और आकर्षक विज्ञापन उन्हें महान नहीं बनाते। उनकी वास्तविक प्रतिष्ठा इस बात से तय होती है कि वे समाज के सबसे कमजोर बच्चे को भी अपने परिसर में समान सम्मान और अवसर देने के लिए कितने तैयार हैं। गौतमबुद्धनगर की यह घटना केवल आरटीई के क्रियान्वयन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा एक नैतिक प्रश्न भी है—क्या शिक्षा आज भी सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, या फिर वह धीरे-धीरे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए आरक्षित एक बंद किला बनती जा रही है? जब तक इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर नहीं मिलता, तब तक 950 से अधिक बच्चों की प्रतीक्षा केवल दाखिले की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि समान अवसर और सामाजिक न्याय की प्रतीक्षा बनी रहेगी। ■

इलेक्ट्रिक बस सेवा से बदलेगा

गौतम बुद्ध नगर का परिवहन परिदृश्य

नोएडा से जेवर तक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तेजी से विकसित हो रहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र को शुक्रवार को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम के जरिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ करते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में 11-11 अत्याधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तीन हाइड्रोजन बसों का संचालन भी प्रारंभ किया गया है, जिनकी संख्या जल्द ही पांच तक बढ़ाई जाएगी।

यह पहल केवल नई बसों के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि नोएडा से लेकर जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक विकसित हो रहे नए आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक गलियारे को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया गया, जो भविष्य की स्मार्ट एवं सतत परिवहन व्यवस्था की आधारशिला साबित होगा।

प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार प्रथम चरण में नोएडा में 50, ग्रेटर नोएडा में 25 तथा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 25 बसों सहित कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। आगामी वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 500 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराया मात्र 20, 30 और अधिकतम 50 रुपये रखा गया है। बसों में पैनिक बटन, लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल सूचना प्रणाली तथा आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शून्य-प्रदूषण आधारित यह परिवहन व्यवस्था वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

इस नई बस सेवा का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने जा रहा है। अब तक सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र के हजारों लोगों को निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत रबूपुरा, दयानतपुर, साबौता, रामनेर, झुडेरा, नीमका, जहाँगीरपुर, बिलासपुर, मिर्जापुर, रोनिजा, मकनपुर खादर, तिलपता, सालारपुर, दनकौर और जेवर सहित अनेक गांव आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएंगे। इससे ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों, कामगारों और छोटे व्यापारियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों तक पहुंच अधिक सुगम एवं किफायती बनेगी।

विशेष महत्व की बात यह है कि इलेक्ट्रिक बसों के कई रूट सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रमुख आवासीय, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक केंद्रों से जोड़ेंगे। इससे हवाई यात्रियों, कर्मचारियों, निवेशकों और पर्यटकों को निर्बाध एवं सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। आने वाले समय में एयरपोर्ट के पूर्ण संचालन के साथ यह बस नेटवर्क क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को और गति प्रदान करेगा।

दरअसल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक्स हब तथा विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के कारण जेवर और आसपास का ग्रामीण क्षेत्र तेजी से विकास की नई धुरी बनकर उभर रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा ने पहली बार यमुना प्राधिकरण के अनेक गांवों को सीधे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहरी केंद्रों से जोड़ने का कार्य किया है। इससे ग्रामीण-शहरी समन्वय मजबूत होगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि संतुलित क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य के स्मार्ट मोबिलिटी मॉडल की मजबूत नींव है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा और वहां से जेवर एयरपोर्ट तक शुरू हुई यह इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन बस सेवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदलते विकास परिदृश्य की नई पहचान बनकर उभर रही है, जो आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र को देश के सबसे आधुनिक और टिकाऊ शहरी-ग्रामीण परिवहन नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। ■

गाँव का नाम था सोनबरसा। छोटा-सा गाँव, लेकिन अपनी मर्यादाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुशासन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध। यहाँ आज भी जब कोई बेटी विदा होती थी तो पूरे गाँव की आँखें नम हो जाती थीं। लोग कहा करते थे—

"गाँव की बेटी पूरे गाँव की लाज होती है और गाँव की इज्जत पूरे समाज का माथा होती है।"

सोनबरसा में चौधरी हरिपाल सिंह का परिवार रहता था। खानदानी लोग थे। जमीन-जायदाद, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान—सब कुछ था। चौधरी हरिपाल की बात पंचायत में अंतिम मानी जाती थी। लोग कहते थे—

"जिस घर के बूढ़े की बात पंचायत में सुनी जाए, समझो उस घर ने पीढ़ियों तक चरित्र कमाया है।"

लेकिन उसी घर में एक लड़का था—अभय।

अभय अपने नाम के विपरीत न निर्भीक था, न जिम्मेदार। वह उन युवाओं में था जिनके लिए जीवन का अर्थ मोबाइल, मोटरसाइकिल और दिखावे तक सीमित हो जाता है। पढ़ाई में मन नहीं, खेती में रुचि नहीं, घर-परिवार की प्रतिष्ठा का बोध नहीं। दिनभर मित्रों के साथ घूमना, नए कपड़े पहनना और सोशल मीडिया पर स्वयं को बड़ा नायक सिद्ध करना उसका काम था।

गाँव के बूढ़े अक्सर कहते—

"जिस बैल के गले में घंटी ज्यादा बजती है, वह हल कम खींचता है।"

इसी बीच उसकी नजर गाँव की दूसरी जाति की लड़की पुष्पा पर पड़ी।

पुष्पा सुंदर थी, चंचल थी, और किशोर मन की स्वाभाविक भावुकता से भरी हुई थी। उसने अभी जीवन को देखा ही कितना था? घर से स्कूल और स्कूल से घर—यही उसकी दुनिया थी।

अभय ने मुस्कराकर बात करनी शुरू की।

फिर कभी रास्ते में मिलना।

फिर मोबाइल पर बातें।

फिर घंटों बातें।

धीरे-धीरे दोनों ने इस आकर्षण को प्रेम का नाम दे दिया।

लेकिन यह प्रेम नहीं था।

प्रेम में त्याग होता है, धैर्य होता है, जिम्मेदारी होती है।

यह तो वैसा ही था जैसे बरसात के पहले आसमान में उठने वाले बादल—घने दिखते हैं, पर बरसते नहीं।

गाँव के मास्टर साहब ने एक दिन अभय को समझाया—

"बेटा! जवानी में देह का आकर्षण प्रेम प्रतीत होता है। परन्तु जब जीवन का बोझ कंधों पर पड़ता है, तब पता चलता है कि प्रेम और आकर्षण में उतना ही अंतर है जितना दीपक और जुगनू में।"

लेकिन जवान खून सलाह नहीं सुनता।

कहावत है—

"जिसे पाँव में चप्पल काटती हो, उसे नंगे पाँव

काँटे का डर नहीं लगता।"

दोनों परिवारों को बात पता चली।

दोनों घरों में जैसे वज्रपात हो गया।

पुष्पा के पिता ने बेटी से कहा—

"बेटी! हम जाति के कारण विरोध नहीं कर रहे। लेकिन समाज की अपनी संरचना होती है, अपनी मर्यादाएँ होती हैं। हर बदलाव केवल विद्रोह से नहीं आता, उसके परिणाम भी होते हैं।"

चौधरी हरिपाल ने भी बेटे से कहा—

"बेटा! मनुष्य अकेला नहीं जीता। वह परिवार, रिश्तों और समाज की डोर से बंधा रहता है। डोर टूट जाए तो पतंग थोड़ी देर उड़ती जरूर है, लेकिन अंत में गिरती ही है।"

लेकिन अभय और पुष्पा को हर सलाह अपनी स्वतंत्रता पर हमला प्रतीत हुई।

एक रात दोनों घर छोड़कर चले गए और शहर में विवाह कर लिया।

समाज में भूचाल आ गया।

गाँव में चौपाल लगी।

लोगों ने कहा—

"समय बदल रहा है।"

दूसरे ने कहा—

"समय बदले तो बदले, लेकिन क्या मर्यादा भी बदल जाए? क्या हर आकर्षण को प्रेम और हर जिद को अधिकार मान लिया जाए?"

गाँव की स्त्रियाँ पुष्पा की माँ को देखकर आह भरतीं।

पुष्पा की माँ ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया।

उधर चौधरी हरिपाल ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया।

एक दिन उन्होंने कहा—

"मैंने जीवनभर जो सम्मान कमाया, वह संपत्ति नहीं था, मेरे पूर्वजों की पूँजी थी।"

कहावत है—

"धन खो जाए तो कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन चरित्र और सम्मान खो जाए तो सब कुछ खो जाता है।"

समय बीतता गया।

शुरुआत के कुछ महीने सपनों जैसे थे।

फिर वास्तविकता सामने आने लगी।

किराया।

राशन।

बीमारी।

नौकरी की अस्थिरता।

सामाजिक अलगाव।

रिश्तेदारों का अभाव।

न कोई त्योहार पर बुलाने वाला, न दुःख में कंधा देने वाला।

धीरे-धीरे आकर्षण का रंग उतरने लगा।

दोनों के घर एक बेटी ने जन्म लिया।

लेकिन बच्ची के जन्म के साथ जिम्मेदारियाँ भी पैदा हुईं।

अब दोनों को एक-दूसरे में गुण नहीं, कमियाँ दिखने लगीं।

अभय सोचता—मैंने क्या पा लिया?

पुष्पा सोचती—जिसे प्रेम समझा था, वह केवल कुछ मीठे शब्द और क्षणिक मोह था।

फिर शुरू हुआ तनाव।

तनाव से झगड़ा।

झगड़े से अपमान।

अपमान से मारपीट।

कहावत है—

"जिस घर में सम्मान मर जाता है, वहाँ प्रेम की चिता जलने में देर नहीं लगती।"

सालों तक यही चलता रहा।

और फिर एक दिन...

रात को केवल दाल में नमक अधिक होने की बात पर विवाद हुआ।

विवाद ने पुराने आरोपों का रूप लिया।

अभय चिल्लाया—

"तुम्हारे कारण मेरा परिवार छूट गया!"

पुष्पा रोते हुए बोली—

"मैंने भी क्या कम खोया? मैंने भी तो अपना घर, अपने माता-पिता, अपना समाज छोड़ा।"

बात बढ़ी।

क्रोध बढ़ा।

और क्रोध विवेक का सबसे बड़ा शत्रु होता है।

सुबह पुलिस को सूचना मिली।

घर के भीतर पुष्पा का शव पड़ा था।

जिस लड़की के लिए अभय ने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, उसी का गला उसके हाथों दबा दिया गया था।

पुलिस उसे ले गई।

गाँव में फिर पंचायत बैठी।

बूढ़े मुखिया ने भारी आवाज में कहा—

"यह हत्या केवल पुष्पा की नहीं हुई है। यह हत्या विवेक की हुई है। यह हत्या मर्यादा की हुई है। यह हत्या उस भ्रम की हुई है जिसमें आज की पीढ़ी आकर्षण को प्रेम और विद्रोह को स्वतंत्रता समझ बैठी है।"

उन्होंने आगे कहा—

"समाज की हर परंपरा पत्थर की लकीर नहीं होती, लेकिन हर परंपरा मूर्खता भी नहीं होती। हजारों वर्षों के अनुभव से कुछ मर्यादाएँ बनती हैं। उन्हें समझे बिना तोड़ देना वैसा ही है जैसे नाव से बीच नदी में तख्ते निकाल देना।"

चौपाल में सन्नाटा था।

पुष्पा की छोटी बेटी अपनी नानी की गोद में बैठी थी।

उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।

वह केवल बार-बार पूछ रही थी—

"माँ कब आएगी?"

उस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था।

सोनबरसा के बूढ़े बरगद की पत्तियाँ हवा में काँप रही थीं।

मानो वे कह रही हों—

"प्रेम कभी हत्या नहीं करता, प्रेम कभी मर्यादा का उपहास नहीं बनाता। जहाँ जिम्मेदारी नहीं, त्याग नहीं, धैर्य नहीं, केवल देह का मोह और क्षणिक आकर्षण है—वहाँ प्रेम नहीं, विनाश का बीज बोया जा रहा होता है।"

और सच भी यही है—

समाज केवल कानून से नहीं चलता, वह मर्यादाओं, विश्वासों और पीढ़ियों से अर्जित मूल्यों पर टिका रहता है। जब नई पीढ़ी बिना समझे हर सीमा को तोड़ने लगती है और पुरानी पीढ़ी संवाद खो देती है, तब सबसे बड़ी कीमत किसी न किसी पुष्पा को अपने प्राण देकर चुकानी पड़ती है। ■

साक्षात्कार : व्यक्ति विशेष

गाजियाबाद की सूरत बदलनी है: नंदकिशोर कलाल

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनके आईएएस बनने का सफर काफी रोचक है। जीडीए वीसी के पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों पर तो सख्त कार्रवाई जारी रखी ही, विकास की भी अनेक परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए पूरी शक्ति लगा रखी है। इसके साथ ही प्राधिकरण को तेरह सौ करोड़ रुपए से चार हजार करोड़ रुपए की आर्थिक क्षमता वाला प्राधिकरण बनाने का प्रयास भी जारी है। पंचायत 24 पत्रिका के संपादक **डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा** और विकास प्राधिकरणों की गतिविधियों पर सतत् दृष्टि रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार तथा पंचायत 24 पत्रिका के सलाहकार संपादक **राजेश बैरागी** ने उनसे साक्षात्कार के दौरान कई अहम् मुद्दों पर प्रश्न पूछे।

प्रश्न: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त होना कैसा अनुभव है?

उत्तर: भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद किसी भी अधिकारी के लिए किसी भी पद पर अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा देना ही लक्ष्य होता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पद मेरे लिए चुनौती कम है, कुछ बेहतर करने का अवसर अधिक है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने नगरीय विकास प्राधिकरणों में से एक है। दिल्ली से सटे इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर को आधुनिक और जनोपयोगी बनाने की जिम्मेदारी इस प्राधिकरण की है। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूं।

प्रश्न: इस प्राधिकरण की स्थापना पहले से बसे हुए एक शहर गाजियाबाद को विस्तार देने तथा नागरिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए की गई थी। स्थापना के लगभग साठ वर्ष बाद वर्तमान में यह प्राधिकरण कहां खड़ा है?

उत्तर: जीडीए ने स्थापना के समय तय किए गए उद्देश्यों को भली प्रकार हासिल किया है। कभी गाजियाबाद चार दरवाजों के बीच बंद एक छोटा सा कस्बा रहा था। जीडीए ने इसे विस्तार देने के साथ एक सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित किया है और शहरवासियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को भी विकसित किया है। गाजियाबाद को अनेक सड़कें, फ्लाईओवर, स्टेडियम, पार्क, मेट्रो, आवासीय, व्यवसायिक और संस्थागत संपत्तियों का विकास, आवंटन तथा लोकार्पण प्राधिकरण ने ही किया है।

प्रश्न: वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा प्रचलित तथा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं

क्या हैं?

उत्तर: वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिंडन एयरपोर्ट के निकट एयरोसिटी, हरनंदीपुरम, इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसी कई महत्वपूर्ण मिश्रित भू-उपयोग की आवासीय योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे इस महानगर की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही शहर से गुजर रहे जीटी रोड को घंटाघर से लेकर लालकुआं तक जाम मुक्त करने के लिए फ्लाईओवर या ऐलेवेटेड रोड बनाए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से डीपीआर तैयार कराई जा रही है। हापुड़ चुंगी चौराहे पर भी फ्लाईओवर बनाने के लिए तैयारी की जा रही है।एन एच -9 से हिंडन एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण लगभग छः किलोमीटर लंबा बाईपास रोड भी बनाया जा रहा है।

प्रश्न: जीडीए की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे?

उत्तर: जीडीए इस महानगर के निवासियों की बहुत सी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है। इसलिए लोगों को थोड़ी बहुत शिकायत हो भी सकती हैं। जीडीए में अधिकारियों कर्मचारियों की कमी भी एक समस्या है। इसके बावजूद मैं स्वयं प्रत्येक कार्य दिवस में जनसुनवाई करता हूं। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सीधे मुझसे मिल सकता है। इसके अलावा एकीकृत समाधान शिविर लगवाए जाते हैं जहां एक ही स्थान पर अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। जटिल प्रकृति के मामलों के लिए अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न: प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण और भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं?

उत्तर: मुझसे पहले से ही अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा था। मैंने भी इस अभियान को जारी रखा है। जीडीए की कॉलोनियों में अवैध निर्माण के प्रति प्राधिकरण की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी प्रकार अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने का अभियान निरंतर

चलाया जा रहा है। प्राधिकरण कर्मियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न: इस शहर में निम्न आय वर्ग तथा नौकरी पेशा लोगों के निवास के लिए प्राधिकरण क्या कर रहा है?

उत्तर: जीडीए ने शुरुआत से ही निम्न आय वर्ग को ध्यान में रखकर आवासीय योजनाएं बनाई हैं।कम कीमत में छोटे किंतु आसानी से रहने योग्य मकान, फ्लैट आदि बनाए गए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित बिल्डर योजनाओं में भी ईडब्ल्यूएस आवास बनवाए जा रहे हैं।जो बिल्डर इसमें हील हुज्जत करते हैं, प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।हाल ही में प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के सैकड़ों फ्लैटों को आवंटियों को निजी तौर पर संपर्क कर उनकी रजिस्ट्री कराई गई है।

प्रश्न: प्राधिकरण को किसानों से भूमि प्राप्त करने में कैसी समस्याएं आ रही हैं?

उत्तर: कोई समस्या नहीं है। किसान अपनी भूमि का उचित मुआवजा चाहते हैं जो उनका अधिकार भी है। प्राधिकरण भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को भूमि के बदले उचित मुआवजा देने के साथ उनकी पीढ़ी के लिए बीस प्रतिशत तक विकसित भूमि भी उपलब्ध कराई जाती है। हरनंदीपुरम योजना के लिए किसान स्वयं चलकर प्राधिकरण आ रहे हैं। किसान भी जानते हैं कि उनके सहयोग के बगैर प्राधिकरण विकास कार्य नहीं कर सकता है। प्राधिकरण भी अपनी विकास योजनाओं में किसानों को सहभागी बनाता है।इसी सहभागिता के उद्देश्य से प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी लैंड पूलिंग पॉलिसी को यथाशीघ्र लागू करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है।

प्रश्न: आपके आईएएस बनने की कहानी क्या है?

उत्तर: मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूं।मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं।उनका सपना मुझे शल्य चिकित्सक बनाने का था। मैंने पीएमटी परीक्षा पास भी कर ली थी परंतु उच्च न्यायालय राजस्थान के एक निर्णय से मेरी रैंकिंग बदल गई और मैं एमबीबीएस से बीडीए में चला गया। इसके बाद मैंने 2011 से यूपीएससी परीक्षा में शामिल होना शुरू किया। तीन प्रयास अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे और चौथा प्रयास तो बिल्कुल ही सिफर रहा। परंतु मैंने हार नहीं मानी और 2017 की यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। ■

अखलाक से सूर्या चौहान तक

क्या अपराधों पर राजनीति का पैमाना बदल जाता है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ घटनाएं केवल आपराधिक मामले नहीं रहतीं, बल्कि वे वैचारिक बहस, राजनीतिक रणनीति और सामाजिक विमर्श का केंद्र बन जाती हैं। वर्ष 2015 का दादरी का अखलाक हत्याकांड और वर्ष 2026 का गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र का सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड दो ऐसी घटनाएं हैं, जिन्होंने अलग-अलग समय में समाज और राजनीति को झकझोरा। दोनों मामलों में एक व्यक्ति की जान गई, दोनों घटनाओं ने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया, दोनों ने कानून-व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन इन पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं में दिखाई देने वाला अंतर आज एक बड़े प्रश्न के रूप में सामने खड़ा है—क्या भारत की राजनीति अपराधों को भी वैचारिक चश्मे से देखने लगी है?

दादरी के बिसहड़ा गांव में सितंबर 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा हत्या ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। घटना के बाद राष्ट्रीय राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता गांव पहुंचे, संसद से लेकर सड़क तक मुद्दा उठाया गया, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में व्यापक चर्चा हुई और देश में बढ़ती असहिष्णुता पर गंभीर प्रश्न उठाए गए। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस घटना की व्याख्या की और यह मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना रहा।

इसके विपरीत, मई 2026 में गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की हत्या ने भी व्यापक जनभावनाओं को प्रभावित किया। आरोपियों की गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु, प्रशासनिक कार्रवाई और कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदमों ने इस मामले को प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला दिया। लेकिन इस घटना पर राष्ट्रीय स्तर पर वैसी राजनीतिक सक्रियता देखने को नहीं मिली जैसी अखलाक मामले में दिखाई दी थी। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक दलों की कथित "सिलेक्टिव अप्रोच" पर बहस शुरू होती है।

भारतीय राजनीति में यह कोई नया आरोप नहीं है कि विभिन्न दल घटनाओं को अपने राजनीतिक

हितों और वैचारिक दृष्टिकोण के अनुसार प्राथमिकता देते हैं। जब किसी घटना से उनके राजनीतिक नैरेटिव को बल मिलता है तो वह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है, जबकि दूसरी घटनाएं अपेक्षाकृत सीमित चर्चा तक सिमट जाती हैं। अखलाक हत्याकांड के समय भाजपा और हिंदुत्व की राजनीति पर तीखे सवाल उठाए गए थे। वहीं सूर्या चौहान हत्याकांड में भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार आक्रामक रुख में दिखाई दी, जबकि विपक्ष की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संयमित रही।

हालांकि इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि किसी भी अपराध की तुलना केवल धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं की जानी चाहिए और प्रत्येक घटना के तथ्य अलग-अलग होते हैं। वहीं भाजपा और उसके समर्थक यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि किसी अपराध को सांप्रदायिक सौहार्द, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वही संवेदनशीलता हर मामले में क्यों नहीं दिखाई देती?

यही प्रश्न आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सार्वजनिक मंचों से कानून-व्यवस्था, अपराध और सांप्रदायिक तनाव से जुड़े मामलों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष सरकार की एनकाउंटर नीति, बुलडोजर कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न उठाता रहा है। इस प्रकार अपराध और राजनीति का यह टकराव केवल दो घटनाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले मुद्दों में शामिल होता दिखाई दे रहा है।

वास्तविक चुनौती यह है कि क्या किसी भी नागरिक की हत्या को उसकी धार्मिक पहचान, राजनीतिक उपयोगिता या वैचारिक संदर्भ से ऊपर उठकर देखा जा सकता है? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही कहता है कि अपराध का मूल्यांकन पीड़ित और आरोपी के धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और न्याय के आधार पर होना चाहिए। यदि किसी एक मामले में मानवाधिकार, न्याय और संवेदनशीलता की मांग उठती है, तो

आभासी तस्वीर

वही मानक दूसरे मामलों पर भी लागू होने चाहिए। अखलाक और सूर्या चौहान—दोनों घटनाएं अलग परिस्थितियों में हुईं, लेकिन दोनों यह याद दिलाती हैं कि किसी भी समाज की परिपक्वता का पैमाना यह नहीं होता कि वह अपने पक्ष के पीड़ितों के लिए कितना बोलता है, बल्कि यह होता है कि वह हर पीड़ित के लिए समान संवेदना और समान न्याय की मांग करता है। राजनीति यदि इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो "सिलेक्टिव आक्रोश" और "सिलेक्टिव मौन" जैसे आरोप लगातार उसके पीछे चलते रहेंगे।

2027 के चुनावी परिदृश्य में यह बहस और तेज हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वही रहेगा—क्या न्याय का पैमाना सभी के लिए समान है, या फिर वह भी राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार बदल जाता है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक दौर में किसी भी आपराधिक घटना का प्रभाव केवल घटनास्थल तक सीमित नहीं रहता। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और चौबीसों घंटे चलने वाले समाचार चैनलों ने घटनाओं को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने की गति कई गुना बढ़ा दी है। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस घटना को कितना प्रचार मिलता है, कौन-से राजनीतिक दल उस पर सक्रियता दिखाते हैं और किस प्रकार का सार्वजनिक नैरेटिव तैयार किया जाता है। कई बार जनमत तथ्यों से अधिक उस प्रस्तुति से प्रभावित होता है, जो विभिन्न माध्यमों के जरिए समाज तक पहुंचती है।भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि प्रत्येक संवेदनशील घटना पर समान मानदंडों के साथ प्रतिक्रिया देना भी है। इसी प्रकार सत्तापक्ष से भी अपेक्षा की जाती है कि वह कानून-व्यवस्था के प्रश्नों को राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर रखकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करे। यदि किसी घटना पर सरकार या विपक्ष की प्रतिक्रिया अलग-अलग परिस्थितियों में बदलती हुई दिखाई देती है, तो इससे राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है और जनता के बीच विश्वास का संकट भी उत्पन्न हो सकता है।इन घटनाओं ने न्याय व्यवस्था की गति और प्रभावशीलता पर भी चर्चा को तेज किया है। किसी भी गंभीर अपराध में शीघ्र जांच, पारदर्शी अभियोजन और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया पीड़ित परिवारों के विश्वास को मजबूत करती है। वहीं यदि न्याय में अनावश्यक विलंब होता है या राजनीतिक बयानबाजी जांच प्रक्रिया पर हावी होने लगती है, तो समाज में भ्रम और अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए कानून का शासन केवल कठोर कार्रवाई से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया से भी स्थापित होता है। ■

व्यवस्था के धृतराष्ट्र और 258 कॉलोनियों का संकट

महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि वह व्यवस्था की विफलता का भी प्रतीक था। हस्तिनापुर का विनाश उस दिन तय हो गया था, जब राजा धृतराष्ट्र ने पुत्रमोह में न्याय और अन्याय के बीच अंतर करना छोड़ दिया था। उनकी शारीरिक अंधता से अधिक घातक उनकी नैतिक अंधता थी। उन्होंने शकुनि की कुटिलता, दुर्योधन के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग को देखते हुए भी अनदेखा किया। परिणामस्वरूप एक समृद्ध साम्राज्य विनाश की आग में झुलस गया।

आज जब गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बसी 258 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, तब महाभारत का वही प्रसंग बरबस याद आता है। फर्क केवल इतना है कि आज के धृतराष्ट्र राजमहलों में नहीं बल्कि व्यवस्था के विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं। वर्षों तक नदी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बसती रहीं, भू-माफिया सक्रिय रहे, प्लॉट बिकते रहे, मकान बनते रहे और लाखों लोगों की जीवन भर की कमाई इन बस्तियों में लगती रही। तब प्रशासन, विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग और स्थानीय निकायों की आंखें आखिर कहां थीं?

आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की सख्ती और पर्यावरणीय चिंताओं के चलते कार्रवाई की तलवार इन कॉलोनियों पर लटक रही है। पर्यावरण संरक्षण निस्संदेह आवश्यक है। हिंडन और यमुना जैसी नदियों का अस्तित्व बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। नदी क्षेत्र में अतिक्रमण बाढ़, जलभराव और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होना भी आवश्यक है।

लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल मकान तोड़ देने से न्याय हो जाएगा? क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी जिनकी निगरानी में ये कॉलोनियां विकसित हुईं? क्या उन भू-माफियाओं और कॉलोनाइजरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर लोगों को सपने बेचे? क्या उन कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अवैध निर्माण होते देखा और फिर भी मौन साधे रखा?

यदि समय रहते प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो शायद आज लाखों लोगों के सिर पर बेघर होने का खतरा नहीं मंडरा रहा होता। जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र की चुप्पी युद्ध का कारण बनी, उसी प्रकार व्यवस्था में बैठे लोगों की अनदेखी और मौन स्वीकृति ने आज इस संकट को जन्म दिया है।

वास्तविक न्याय तभी होगा जब बुलडोजर केवल ईंट-पत्थरों पर नहीं, बल्कि उस भ्रष्ट तंत्र पर भी चले जिसने इस अवैध साम्राज्य को खड़ा होने दिया। यदि कार्रवाई केवल गरीब और मध्यमवर्गीय मकान मालिकों तक सीमित रही और असली दोषी बच निकले और अवसर पाकर फिर व्यवस्था का दुरूपयोग कर आम जनता को संकट में डालेंगे। वैसे में यह न्याय नहीं बल्कि व्यवस्था की एक और अफलता होगी।

गाजियाबाद की 258 कॉलोनियों का मुद्दा केवल अवैध निर्माण का नहीं है। यह प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक संरक्षण, भ्रष्टाचार और व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न है। इतिहास गवाह है कि जब-जब व्यवस्था के धृतराष्ट्र अपनी आंखें बंद करते हैं, तब-तब समाज को महाभारत जैसी त्रासदियों का सामना करना पड़ता है।

आज आवश्यकता केवल अतिक्रमण हटाने की नहीं, बल्कि उन धृतराष्ट्रों की पहचान करने की भी है जिनकी चुप्पी और स्वार्थ ने इस संकट को जन्म दिया। तभी पर्यावरण भी बचेगा, कानून का सम्मान भी होगा और आम नागरिक का विश्वास भी कायम रहेगा। ■

पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान नवाब सिंह नागर के हाथ : अवसर शानदार, चुनौतियाँ भी कम नहीं

भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से चल रही राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाते हुए उत्तर प्रदेश संगठन की नई टीम तथा क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस पुनर्गठन में पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान वरिष्ठ गुर्जर नेता नवाब सिंह नागर को सौंपना केवल एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति का महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तथा विभिन्न दल प्रभावशाली सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की प्रतिस्पर्धा में जुटे हैं।

पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुर्जर समाज अनेक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक संतुलन के माध्यम से अपने चुनावी आधार को और सुदृढ़ करना चाहती है।

यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने दादरी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी रैली आयोजित कर गुर्जर समाज के बीच अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास किया था।

नवाब सिंह नागर का सार्वजनिक जीवन संघर्ष, संगठन और जनसंपर्क की लंबी यात्रा का परिचायक रहा है। छात्र एवं सामाजिक गतिविधियों से लेकर संगठनात्मक दायित्वों तक उन्होंने निरंतर सक्रिय भूमिका निभाई। दादरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में लगातार दो बार विजय प्राप्त कर उन्होंने न केवल अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता सिद्ध की, बल्कि दादरी सीट पर भाजपा का विजय खाता खोलने का श्रेय भी उनके नाम दर्ज हुआ। यद्यपि बाद के वर्षों में वे सक्रिय चुनावी राजनीति के केंद्र से कुछ दूर रहे, किंतु संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सक्रियता कभी कम नहीं हुई।

इसी दीर्घ अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक स्वीकार्यता को आधार बनाकर पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसी राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी नियुक्ति भाजपा को संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।

किन्तु यह दायित्व जितना सम्मानजनक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। नवाब सिंह नागर की राजनीतिक कर्मभूमि गौतम बुद्ध नगर लंबे समय से भाजपा की आंतरिक गुटबाज़ी और अंतर्कलह का केंद्र रही है। विडंबना यह रही कि वे स्वयं कभी इन परिस्थितियों का हिस्सा रहे तो कभी इससे प्रभावित भी रहे। समय-समय पर यह अंतर्विरोध सार्वजनिक रूप से सामने आता रहा है, जिससे संगठनात्मक ऊर्जा का क्षरण हुआ और पार्टी की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगे।

ऐसी परिस्थितियों में नवाब सिंह नागर के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती केवल संगठन का विस्तार करना नहीं, बल्कि संगठन को एक सूत्र में पिरोना होगी। कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास, संवाद और समन्वय स्थापित करना उनके नेतृत्व की वास्तविक कसौटी बनेगा। यदि वे पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक अनुशासन, सामंजस्य और सामूहिक नेतृत्व की संस्कृति विकसित करने में सफल होते हैं, तो यह भाजपा के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी सिद्ध हो सकता है।

अब राजनीतिक हलकों की निगाहें केवल इस बात पर नहीं हैं कि नवाब सिंह नागर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी स्थिति को कितना मजबूत कर पाएंगे, बल्कि इस प्रश्न पर भी केंद्रित हैं कि क्या वे गौतम बुद्ध नगर से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वर्षों से चली आ रही गुटबाज़ी की राजनीति पर विराम लगाकर संगठन को नई दिशा दे पाएंगे, अथवा वह स्वयं भी उसी अंतर्कलह का हिस्सा बनकर गुटबाजी की एक दशक पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल उनके नेतृत्व की शैली ही नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की भावी राजनीतिक दिशा भी तय करेगा। ■

मोबाइल की कैद में बचपन: अदृश्य खेल, अदृश्य हत्यारे और टूटते परिवार

गाजियाबाद से उठी वह चीख, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया"सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी…" आठ पन्नों की एक डायरी में लिखे ये शब्द केवल तीन मासूम बेटियों के आखिरी वाक्य नहीं हैं, बल्कि डिजिटल युग के उस भयावह सच की दस्तक हैं, जो धीरे-धीरे हमारे घरों, बच्चों और परिवारों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है।

गाजियाबाद की भारत सिटी सोसायटी की नौवीं मंजिल से 16, 14 और 12 वर्ष की तीन बहनों का एक साथ छलांग लगाना महज एक आत्महत्या नहीं, बल्कि हमारे समय का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट है। यह घटना हमें बताती है कि मोबाइल की छोटी-सी स्क्रीन के भीतर एक ऐसी आभासी दुनिया भी बसती है, जो कभी-कभी बच्चों के वास्तविक जीवन से भी बड़ी हो जाती है।

जब मोबाइल खिलौना नहीं, नियति बन जाता है

कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर लाखों बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन आया। शुरुआत पढ़ाई से हुई, लेकिन धीरे-धीरे सोशल मीडिया, गेमिंग और वर्चुअल दुनिया ने बचपन की मासूमियत को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया।

गाजियाबाद की तीनों बच्चियां कथित रूप से एक टास्क आधारित कोरियाई 'लव गेम' से प्रभावित थीं। पुलिस जांच जारी है और किसी ऐप की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वे आभासी दुनिया से इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना चुकी थीं कि वास्तविक जीवन उन्हें बोझ लगने लगा था।

यही डिजिटल लत की सबसे खतरनाक अवस्था है—जब व्यक्ति स्क्रीन पर बने रिश्तों को असली और अपने परिवार को पराया समझने लगे।

अदृश्य कदमों से आती है बर्बादी

कोई भी बच्चा एक दिन में गेमिंग का आदी नहीं बनता। यह लत बहुत धीरे-धीरे, अदृश्य कदमों से घर में प्रवेश करती है।

पहले एक घंटा…

फिर दो घंटे…

फिर रातों की नींद…

फिर परिवार से दूरी…

फिर पढ़ाई से अरुचि…

और अंततः वास्तविक दुनिया से विच्छेद।

बच्चे हंसना भूल जाते हैं, दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, खेल के मैदान खाली हो

जाते हैं और कमरे की चार दीवारें तथा मोबाइल की स्क्रीन उनकी पूरी दुनिया बन जाती है।

गाजियाबाद की बच्चियों की दीवारों पर लिखे वाक्य—"आई एम वेरी वेरी अलोन"—दरअसल आज की पूरी पीढ़ी की मौन पीड़ा हैं।

गेम नहीं, दिमाग का जाल

ऑनलाइन गेम केवल मनोरंजन नहीं हैं। वे मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित होते है।

हर लेवल पार करने पर पुरस्कार...

हर टास्क पूरा करने पर उत्साह...

हर नोटिफिकेशन पर डोपामिन का स्राव...

दिमाग बार-बार उसी सुख की तलाश करता है। धीरे-धीरे मोबाइल एक आदत नहीं, आवश्यकता बन जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'गेमिंग डिसऑर्डर' को मानसिक स्वास्थ्य समस्या माना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गेमिंग बच्चों में अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन, सामाजिक अलगाव और आत्मघाती विचारों तक को जन्म दे सकती है।

गाजियाबाद अकेला नहीं है...

गाजियाबाद की घटना देश की पहली त्रासदी नहीं है।

- इंदौर में एक सातवीं कक्षा के छात्र ने गेम में पैसे हारने के बाद आत्महत्या कर ली।
- राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज से परेशान दंपती ने जान दे दी।
- बिजनौर के कारोबारी ने एक करोड़ रुपये गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली।
-कुशीनगर के छात्र ने गेमिंग की लत से परेशान होकर फांसी लगा ली।

इन घटनाओं की कड़ियां अलग-अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनका केंद्र एक ही है—डिजिटल लत और भावनात्मक अकेलापन।

बर्बाद होता परिवार, टूटते रिश्ते

जब कोई बच्चा ऑनलाइन दुनिया में खो जाता है तो केवल उसका बचपन नहीं मरता, पूरा परिवार टूट जाता है।

माता-पिता अपराधबोध में जीते हैं। भाई-बहनों पर मानसिक प्रभाव पड़ता है। घर में हंसी की जगह सन्नाटा बस जाता है।गाजियाबाद में तीन बेटियों की मौत के बाद जिस परिवार में कभी पांच बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां आज केवल सिसकियां हैं।

एक मोबाइल डिवाइस ने तीन जिंदगियां ही नहीं छीनीं, एक पूरे परिवार का भविष्य निगल लिया।

क्या हम अपने बच्चों को खो रहे हैं?

यह सवाल केवल गाजियाबाद के माता-पिता से नहीं, पूरे समाज से पूछा जाना चाहिए।

हम बच्चों को महंगे स्मार्टफोन दे रहे हैं, लेकिन समय नहीं।

इंटरनेट दे रहे हैं, लेकिन संवाद नहीं। मनोरंजन दे रहे हैं, लेकिन भावनात्मक सहारा नहीं।

बच्चे स्क्रीन से जुड़ रहे हैं और परिवार से कट रहे हैं। समाधान क्या है?

बचपन को बचाना केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, यह परिवार, स्कूल और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

- छोटे बच्चों को अनियंत्रित स्मार्टफोन न दें।
- स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा तय करें।
- बच्चों की डिजिटल गतिविधियों में रुचि लें।
- उनसे रोज खुलकर बातचीत करें।
- खेल, पुस्तक, संगीत और मित्रता को प्रोत्साहित करें।
- अकेलापन, चिड़चिड़ापन और व्यवहार में बदलाव को नजरअंदाज न करें।
- जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक सहायता लेने में संकोच न करें।

अंत में...

गाजियाबाद की नौवीं मंजिल से गिरने वाली तीन बच्चियां केवल एक परिवार की बेटियां नहीं थीं; वे इस डिजिटल युग के उस मासूम बचपन की प्रतीक हैं, जो धीरे-धीरे मोबाइल की नीली रोशनी में खोता जा रहा है।

यदि हमने समय रहते इस खतरे को नहीं समझा, तो आने वाले वर्षों में हमारे घरों में खिलौने तो होंगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन उनका बचपन नहीं होगा।

और तब शायद किसी और डायरी के आखिरी पन्ने पर फिर लिखा होगा—

"सॉरी पापा... आई एम रियली सॉरी..."

क्योंकि आज का सबसे बड़ा अदृश्य हत्यारा कोई वायरस नहीं, बल्कि वह डिजिटल लत है, जो मुस्कुराते चेहरों के पीछे धीरे-धीरे बचपन, परिवार और भविष्य—तीनों को निगल रही है। ■

कॉकरोच पार्टी: युवाओं के आक्रोश की अभिव्यक्ति या राजनीति का नया प्रयोग?

डिजिटल युग में राजनीति का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब किसी विचार को जनचर्चा का विषय बनाने के लिए न बड़े संगठन की आवश्यकता है और न ही वर्षों की राजनीतिक तैयारी की। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी विचार, प्रतीक या अभियान कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है। हाल के दिनों में चर्चा में आई "कॉकरोच जनता पार्टी" (सीजेपी) इसी प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण है। यह अभी तक कोई औपचारिक राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी उपस्थिति, युवाओं की भागीदारी और व्यवस्था विरोधी विमर्श ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है।

एक टिप्पणी से आंदोलन तक का सफर

कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा उस समय शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान न्यायपालिका की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुई। इसके बाद कुछ युवाओं और डिजिटल एक्टिविस्टों ने "कॉकरोच" शब्द को विरोध और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया।

इस अभियान को प्रमुखता से आगे बढ़ाने वालों में राजनीतिक संचार विशेषज्ञ अभिजीत दिपके का नाम सामने आया। उन्होंने इसे युवाओं की निराशा, बेरोजगारी और अवसरों की कमी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक आंदोलन बताया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि आंदोलन के कुछ प्रमुख चेहरे पहले से राजनीतिक अभियानों और वैचारिक समूहों से जुड़े रहे हैं, जिसके कारण इसकी राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

कॉकरोच ही क्यों?

किसी भी आंदोलन की पहचान उसके प्रतीक से बनती है। कॉकरोच पार्टी के समर्थकों के अनुसार कॉकरोच ऐसा जीव है जो सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। उनके अनुसार आज का युवा भी आर्थिक चुनौतियों, रोजगार संकट और अनिश्चित भविष्य के बीच संघर्ष कर रहा है। समर्थकों का मानना है कि जिस शब्द का प्रयोग अपमान के रूप में किया गया, उसे ही प्रतिरोध और आत्मसम्मान के प्रतीक में बदल देना इस अभियान का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरी ओर आलोचक इसे गंभीर राजनीतिक विमर्श के बजाय प्रतीकात्मक और भावनात्मक राजनीति का उदाहरण मानते हैं।

युवाओं के कौन से मुद्दे हैं केंद्र में?

कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता का आधार मुख्यतः युवाओं से जुड़े वे मुद्दे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चा में रहे हैं—

- बेरोजगारी और रोजगार के सीमित अवसर
- प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक
- NEET, CUET तथा अन्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े विवाद
- सरकारी भर्तियों में देरी
- बढ़ती महंगाई
- शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी

युवाओं का एक वर्ग मानता है कि पारंपरिक राजनीतिक दल इन मुद्दों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। इसी भावना ने इस डिजिटल अभियान को गति दी है।

क्या यह नया अन्ना आंदोलन बन सकता है?

कॉकरोच पार्टी की तुलना स्वाभाविक रूप से 2011 के अन्ना आंदोलन से की जा रही है। दोनों आंदोलनों में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, युवाओं की भागीदारी और व्यवस्था के प्रति असंतोष जैसे समान तत्व दिखाई देते हैं।

लेकिन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। अन्ना आंदोलन के पास स्पष्ट नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचा और भ्रष्टाचार विरोधी एक केंद्रीय एजेंडा था। वहीं कॉकरोच पार्टी फिलहाल एक प्रतीकात्मक और डिजिटल अभियान के रूप में अधिक दिखाई देती है। उसके पास अभी कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम या व्यापक संगठनात्मक संरचना नहीं है।

राजनीतिक समर्थन और विवाद

आंदोलन के विस्तार के साथ कई विपक्षी नेताओं, छात्र संगठनों और सरकार विरोधी समूहों ने इसके प्रति सहानुभूति दिखाई। इससे यह धारणा बनी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसे सत्ताविरोधी जनभावनाओं के संभावित मंच के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके बावजूद आंदोलन के कुछ प्रमुख समर्थकों की पूर्व राजनीतिक सक्रियता और विपक्षी विमर्श से निकटता को लेकर बहस जारी है। यही कारण है कि समर्थक इसे युवाओं की स्वतःस्फूर्त आवाज बताते हैं, जबकि विरोधी इसे एक सुविचारित राजनीतिक प्रयोग मानते हैं।

दुनिया में ऐसे प्रयोग कितने सफल रहे?

विश्व राजनीति में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जिन्होंने व्यंग्य, प्रतीक और जनअसंतोष को राजनीतिक शक्ति में बदलने का प्रयास किया।

आइसलैंड की "बेस्ट पार्टी" ने पारंपरिक राजनीति के खिलाफ व्यंग्य को हथियार बनाया और स्थानीय चुनावों में सफलता हासिल की। इटली का "फाइव स्टार मूवमेंट" सोशल मीडिया आधारित जनआंदोलन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण शक्ति बन गया।

वहीं यूक्रेन में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग ने एक गैर-पारंपरिक नेतृत्व को सत्ता तक पहुंचाया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि केवल असंतोष पर्याप्त नहीं होता। दीर्घकालिक सफलता के लिए संगठन, नेतृत्व, स्पष्ट नीतियां और जनता का निरंतर विश्वास आवश्यक होता है।

क्या भारत में भी बड़ा राजनीतिक बदलाव संभव है?

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी समूहों को उम्मीद है कि भारत का जेन-जी भी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह बड़े राजनीतिक परिवर्तन का आधार बन सकता है। हालांकि भारत की परिस्थितियां इन देशों से काफी अलग हैं। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं, नियमित चुनाव, संघीय व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हैं। इसलिए किसी डिजिटल आंदोलन के आधार पर बड़े राजनीतिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

भारत का जेन-जी कितना अलग है?

भारतीय युवा वर्ग की प्राथमिकताएं केवल वैचारिक राजनीति तक सीमित नहीं हैं। रोजगार, शिक्षा, तकनीक, उद्यमिता और आर्थिक अवसर उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं।

यही कारण है कि सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन की लोकप्रियता को सीधे चुनावी समर्थन में बदल देना आसान नहीं होता। भारतीय युवा भावनात्मक नारों के साथ-साथ ठोस नीतिगत विकल्पों और विकास के अवसरों को भी महत्व देते हैं।

भविष्य की राजनीति का संकेत या क्षणिक उभार?

कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल एक राजनीतिक दल से अधिक एक प्रतीकात्मक आंदोलन है। इसने बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा और अवसरों जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया है।

लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह सोशल मीडिया अभियान से आगे बढ़कर कोई संगठनात्मक ढांचा, नेतृत्व और वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टि विकसित कर पाती है या नहीं।

कॉकरोच जनता पार्टी आज की युवा पीढ़ी के भीतर मौजूद बेचैनी, असंतोष और अपेक्षाओं का प्रतीक बनकर उभरी है। यह आंदोलन चाहे राजनीतिक विकल्प बने या केवल डिजिटल प्रतिरोध का प्रतीक रह जाए, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा कर दिया है—क्या भारत का युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से संतुष्ट है या वह अपने लिए एक नए राजनीतिक मंच की तलाश कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ■

गंगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का नया इंजन

मेरठ से प्रयागराज तक फैला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक भूगोल को बदलने वाला विकास का महागलियारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित यह एक्सप्रेसवे प्रदेश सरकार के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को नई गति देने जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि, श्रम व सेवा आधारित अर्थव्यवस्था को जोड़ते हुए विकास की नई धारा प्रवाहित करेगी।

सड़क नहीं, आर्थिक परिवर्तन का कॉरिडोर

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 12 जिलों को जोड़ता है। यह वही क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी निवास करती है और जहां कृषि, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, खेल सामग्री, टेक्सटाइल तथा हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था मौजूद है। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति में तेज कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेहतर सड़क नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स लागत घटती है, निवेश आकर्षित होता है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। गंगा एक्सप्रेसवे इन तीनों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बड़ी बढ़त देने वाला साबित हो सकता है।

पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच विकास का सेतु

पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि, मानव संसाधन और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब तक दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी और परिवहन की चुनौतियां विकास की गति को सीमित करती थीं। गंगा एक्सप्रेसवे इस असंतुलन को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग, उन्नाव का लेदर सेक्टर, हरदोई का हैंडलूम, प्रतापगढ़ का आंवला उद्योग और प्रयागराज का पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र अब एक साझा आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा बन सकेंगे। इससे उत्पादों की आवाजाही तेज होगी और बाजारों तक पहुंच

आसान बनेगी।

ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को कैसे मिलेगी रफ्तार?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा आधार है। गंगा एक्सप्रेसवे इसी रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना पांच स्तरों पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देगी—

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: मेरठ से प्रयागराज की यात्रा 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6-7 घंटे रह जाएगी। औद्योगिक निवेश में वृद्धि: एक्सप्रेसवे किनारे विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर निवेशकों को आकर्षित करेंगे। रोजगार सृजन: निर्माण, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। कृषि को लाभ: किसानों के उत्पाद कम समय में बाजार तक पहुंचेंगे, जिससे बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। पर्यटन और धार्मिक अर्थव्यवस्था का विस्तार: प्रयागराज, काशी और गंगा तटवर्ती क्षेत्रों तक पहुंच आसान होने से पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी।

27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बदलेंगे आर्थिक तस्वीर

गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे केवल परिवहन परियोजना के रूप में नहीं देखा गया है। इसके किनारे 27 इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। यह मॉडल विकसित देशों के आर्थिक कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब सड़क, उद्योग और लॉजिस्टिक्स एक साथ विकसित होते हैं तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि होती है। इससे छोटे शहरों में भी निवेश पहुंचता है और रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं।

किसानों की भागीदारी से बनी विकास की धारा

गंगा एक्सप्रेसवे की एक विशेष उपलब्धि यह भी है कि इसके निर्माण में 12 जिलों के एक लाख से अधिक किसानों ने भूमि उपलब्ध कराकर सहयोग दिया। लगभग 18 हजार एकड़ भूमि एक्सप्रेसवे के लिए और करीब 7 हजार एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित की गई है। विशेषज्ञ इसे "पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल" का सफल उदाहरण मानते हैं, जहां किसानों की भागीदारी से एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी हुई।

एक्सप्रेसवे स्टेट बनने की ओर उत्तर प्रदेश

वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में सबसे व्यापक एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे मिलकर राज्य को उत्तर भारत का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं तो उत्तर प्रदेश अगले दशक में देश की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे केवल मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाला राजमार्ग नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच विकास का सेतु बनकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि एक्सप्रेसवे के साथ प्रस्तावित औद्योगिक और लॉजिस्टिक परियोजनाएं भी निर्धारित समय में विकसित होती हैं, तो गंगा एक्सप्रेसवे वास्तव में उत्तर प्रदेश की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की यात्रा का सबसे मजबूत इंजन साबित हो सकता है। ■

देश से लेकर प्रदेश की राजधानी तक... : अग्निकांड में

जलते लोग उठते सवाल

नई दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी क्षेत्र में स्थित फ्लोरिश स्टे होटल से उठती चीखें हों या लखनऊ के अलीगंज में आग से घिरी इमारत में फंसे छात्रों की अंतिम पुकार—दोनों घटनाओं की तस्वीरें अलग थीं, लेकिन दर्द एक जैसा था। दोनों जगह लोग खिड़कियों से मदद मांग रहे थे, धुएं में दम घुट रहा था, लोग जान बचाने के लिए ऊंची मंजिलों से छलांग लगाने को मजबूर थे और अंत में दर्जनों परिवारों के सपने राख में बदल गए।

दिल्ली में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लखनऊ में 15 छात्र-छात्राओं ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इन दोनों घटनाओं का सबसे भयावह पहलू मृतकों की संख्या नहीं, बल्कि वह व्यवस्था है जिसने इन मौतों को संभव बनाया।

दो राजधानियां... एक जैसी त्रासदी, एक जैसी लापरवाही

दिल्ली के मालवीय नगर में जिस बी एंड बी को केवल छह कमरों के संचालन की अनुमति थी, वहां लगभग 25 कमरे चल रहे थे। फायर एनओसी नहीं थी, बेसमेंट का उपयोग नियमों के विपरीत हो रहा था, आपातकालीन निकास नहीं था और भवन की संरचना लोगों के लिए मौत का जाल बन गई।

लखनऊ में एक ही इमारत में पेट शॉप, ज्वलनशील सामान का वेयरहाउस, कोचिंग सेंटर और एनीमेशन प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहा था। वैकल्पिक निकास का अभाव, अग्नि सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम और कथित रूप से राहत सेवाओं की देरी ने स्थिति को और भयावह बना दिया। दोनों घटनाएं एक ही प्रश्न पूछती हैं—क्या लोग आग से मरे या फिर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और नियमों के चयनात्मक पालन ने उन्हें मौत के मुंह में धकेला?

हर हादसे के बाद सिस्टम की वही पुरानी पटकथा

हमारे यहां लगभग हर बड़े अग्निकांड के बाद घटनाक्रम तयशुदा होता है— मंत्रियों और बड़े अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का दौरा, मुआवजे

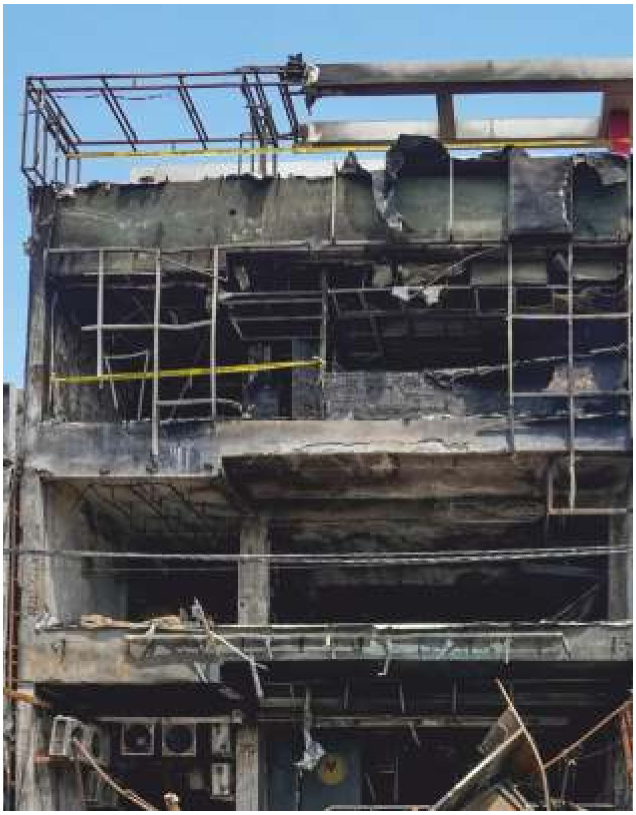

की घोषणा, उच्चस्तरीय जांच, कुछ अधिकारियों का निलंबन, कुछ गिरफ्तारियां, सख्त कार्रवाई के दावे और फिर... समय के साथ सब कुछ फाइलों की धूल में दफन।

लखनऊ इसका जीवंत उदाहरण है। 2018 में एसएसजे इंटरनेशनल और विराट होटल अग्निकांड में नौ लोगों की मौत हुई। 2022 में होटल लेवाना सुइट्स में चार लोग जिंदा जल गए। 2025 में लोकबंधु अस्पताल, सरोजनीनगर फूड फैक्टरी और कपूरथला की घटनाओं ने आग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। 2026 में विकासनगर की झुग्गियों में दो बच्चों की मौत हुई और अब अलीगंज की त्रासदी सामने है।

दिल्ली में भी यह पहला बड़ा हादसा नहीं है। मालवीय नगर अग्निकांड ने फिर उजागर किया कि राजधानी में अवैध निर्माण, बिना एनओसी चल रहे प्रतिष्ठान और कमजोर निरीक्षण तंत्र आज भी गंभीर खतरा बने हुए हैं। घटनाएं बदलती रहीं, मृतकों के नाम बदलते रहे, लेकिन सिस्टम का चरित्र नहीं बदला, आखिर जिम्मेदार कौन? क्या केवल भवन मालिक दोषी है? यदि किसी होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी, तो वह वर्षों तक कैसे संचालित होता रहा? यदि किसी भवन में अवैध निर्माण था, तो निरीक्षण एजेंसियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? यदि कोचिंग संस्थान, वेयरहाउस और अन्य गतिविधियां एक ही भवन में चल रही थीं, तो संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित हैं? क्या नियम केवल छोटे लोगों के लिए हैं? क्या जवाबदेही केवल हादसे के बाद बयान देने तक सीमित है?

आग केवल इमारतों में नहीं लगी...

सच्चाई यह है कि दिल्ली और लखनऊ की ये घटनाएं केवल अग्निकांड नहीं हैं; ये हमारे शहरी प्रशासन, भवन नियमन, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही की सामूहिक विफलता की चार्जशीट हैं। जगजाहिर है कि अवैध निर्माण राजनीतिक संरक्षण में पनपते हैं। फायर एनओसी कागजी औपचारिकता बन जाती है।निरीक्षण अक्सर खानापूर्ति में बदल जाते हैं। नोटिस जारी होते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती।

और जब त्रासदी होती है, तब उसकी कीमत आम नागरिक अपनी जान देकर चुकाते हैं।

मौत के बाद मुआवजा... क्या यही शासन का अंतिम समाधान है?

हर अग्निकांड के बाद आर्थिक सहायता की घोषणा की जाती है। यह आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। किसी मां की सूनी गोद, किसी पिता की टूटी उम्मीद, किसी बच्चे का भविष्य और किसी परिवार की खुशियां मुआवजे से वापस नहीं आतीं। देश को मुआवजे से अधिक जवाबदेही की जरूरत है। उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें अवैध निर्माण बनने से पहले रोके जाएं, बिना एनओसी भवनों को सील किया जाए, निरीक्षण व्यवस्था पारदर्शी बने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो।

लाचार और बेबस सिस्टम... फिर अगली त्रासदी का इंतजार?

दिल्ली और लखनऊ की राख से उठता सबसे बड़ा प्रश्न यही है - क्या हमारा सिस्टम केवल हादसों के बाद सक्रिय होने के लिए बना है? क्या जांच समितियां केवल जनाक्रोश शांत करने का माध्यम हैं? क्या हम हर अग्निकांड के बाद कुछ दिनों का शोक मनाकर अगली आग, अगली चीख और अगली मौत का इंतजार करने लगते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है—आग अचानक नहीं लगती। उसे वर्षों तक लापरवाही, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही के अभाव की चिंगारियां सुलगाती रहती हैं।

और जब आग भड़कती है, तब केवल इमारतें नहीं जलतीं—व्यवस्था की संवेदनशीलता, शासन की तैयारियां और प्रशासन की विश्वसनीयता भी राख हो जाती है। सवाल आज भी वही है—आखिर लापरवाही की चिता पर कब तक लोग जिंदा जलते रहेंगे और हमारा सिस्टम कब तक अगली बड़ी त्रासदी का इंतजार करता रहेगा? ■

राम के नाम पर बना मंदिर माया के साये में खड़े सवाल

क्या हम राम का भव्य मंदिर तो बना पाए, लेकिन राम की मर्यादा और आदर्शों की रक्षा कर पाए?

भारतीय सभ्यता में भगवान राम केवल एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन हैं। वे त्याग हैं, मर्यादा हैं, सत्य हैं, लोककल्याण हैं और सबसे बढ़कर सत्ता के ऊपर नैतिकता की स्थापना का आदर्श हैं। रामराज्य की कल्पना में केवल समृद्धि नहीं, बल्कि पारदर्शिता, न्याय, जवाबदेही और जनविश्वास का भी समावेश है। यही कारण है कि अयोध्या में निर्मित श्रीराम मंदिर करोड़ों भारतीयों के लिए मात्र एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ऐतिहासिक न्याय और राष्ट्रीय आत्मगौरव का प्रतीक बन गया।

लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य तब जन्म लेता है, जब किसी आदर्श के नाम पर बनी व्यवस्था उसी आदर्श की कसौटी पर कठघरे में खड़ी दिखाई देने लगे। श्रीराम मंदिर के चढ़ावे, दानराशि, जेवरात, गणना प्रक्रिया और प्रबंधन संबंधी कथित अनियमितताओं की खबरों ने देश के सामने केवल वित्तीय गड़बड़ी का प्रश्न नहीं रखा है। इसने एक बड़ा नैतिक और वैचारिक प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या राम के नाम पर जुटी आस्था का प्रबंधन भी राम के आदर्शों के अनुरूप है?

भारतीय जनमानस में यह मंदिर पांच सौ वर्षों के संघर्ष, बलिदान और प्रतीक्षा का प्रतिफल है। अनगिनत लोगों ने राम मंदिर आंदोलन को केवल धार्मिक प्रश्न नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न के रूप में जिया। भारतीय जनता पार्टी और व्यापक राष्ट्रवादी विचारधारा ने भी दशकों तक राम मंदिर को अपने वैचारिक विमर्श के केंद्र में रखा। राम केवल चुनावी मुद्दा नहीं थे; वे सांस्कृतिक पुनर्स्थापना, सभ्यतागत स्मृति और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक थे।

यही कारण है कि यदि राम मंदिर प्रबंधन पर प्रश्न उठते हैं, तो उसका प्रभाव केवल किसी ट्रस्ट, कर्मचारी या अधिकारी तक सीमित नहीं रहता। यह उस नैतिक पूंजी को भी प्रभावित करता है, जो वर्षों से राम के नाम पर निर्मित हुई है।

राजनीति में प्रतीक अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन प्रतीकों की शक्ति उनके नैतिक आधार से आती है। यदि वही आधार कमजोर पड़ने लगे, तो राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव भी पड़ना स्वाभाविक है। चुनावी दृष्टि से देखें तो इस प्रकार के विवाद उन लोगों को भी प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं, जिन्होंने राम मंदिर को अपने विश्वास का केंद्र बनाया था। विपक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता

के मुद्दे के रूप में उठाएगा, जबकि सत्ता पक्ष के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी—अवसर इसलिए कि वह निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई के माध्यम से विश्वास बहाल करे, और चुनौती इसलिए कि राम के नाम से जुड़ी किसी भी संस्था पर लगा प्रश्न सामान्य प्रशासनिक विवाद से कहीं अधिक संवेदनशील होता है।

भारतीय लोकजीवन में एक कहावत है—"जैसा राजा, वैसी प्रजा; और जैसा आदर्श, वैसी व्यवस्था।" यदि राम आदर्श हैं, तो व्यवस्था भी मर्यादित, पारदर्शी और उत्तरदायी होनी चाहिए।

कबीर ने लिखा था—

"माया महा ठगिनी हम जानी..."

यहीं इस पूरे प्रकरण का सबसे गहरा दार्शनिक पक्ष सामने आता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राम के नाम का जप करने वाले लोग, यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो माया के आकर्षण में राम की मर्यादा को ही भूल बैठे? क्या आस्था की रक्षा का दायित्व निभाने वाली व्यवस्थाओं में कहीं धन, प्रभाव और निकटता ने उत्तरदायित्व पर भारी पड़ने की कोशिश की? ये प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक हैं।

भारतीय परंपरा में मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं होता; वह लोकधन और लोकविश्वास का तीर्थ होता है। किसान जब अपनी उपज का एक हिस्सा चढ़ाता है, मजदूर अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ रुपये अर्पित करता है, व्यापारी अपनी आय का हिस्सा दान करता है, तब वह केवल पैसा नहीं देता—वह अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपनी आशा समर्पित करता है। इसलिए कहा जाता है—

"धन की चोरी की भरपाई हो सकती है, विश्वास की चोरी की नहीं।"

यदि जांच में उठे प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं मिलते, तो सबसे बड़ी क्षति किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल की नहीं होगी; सबसे बड़ी क्षति उस विश्वास की होगी, जो सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला के चरणों में पुनः स्थापित हुआ है।

इतिहास गवाह है कि बड़े संस्थान बाहर से कम और भीतर की कमजोरियों से अधिक टूटते हैं।

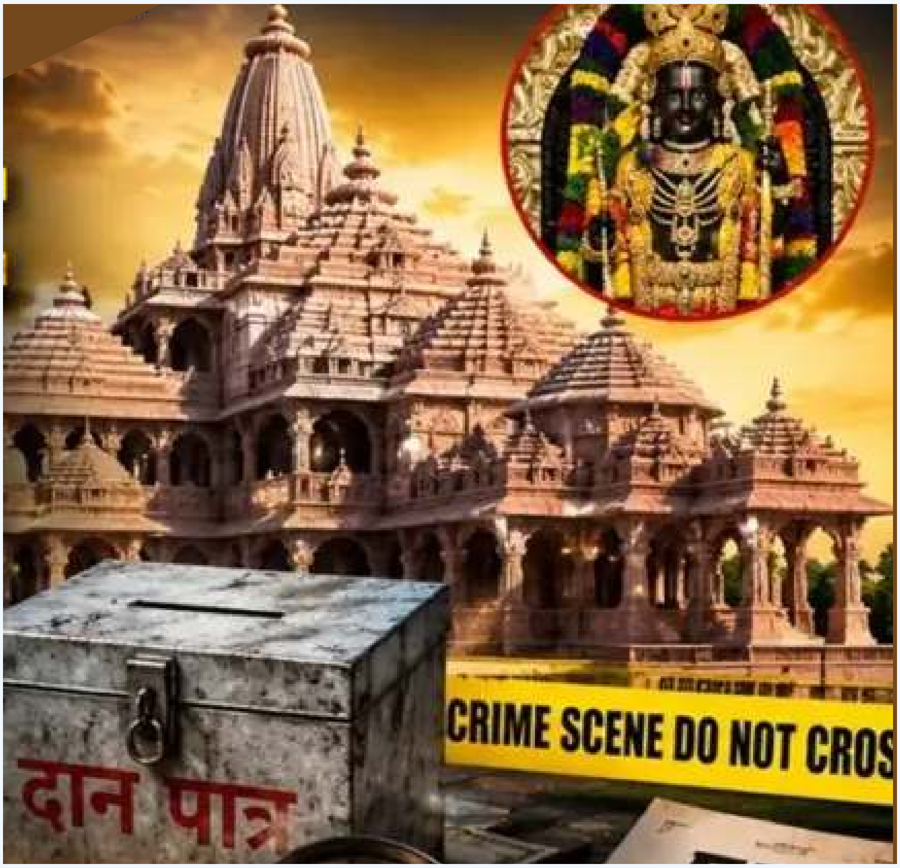

मंदिरों की दीवारें पत्थरों से बनती हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पारदर्शिता, ईमानदारी और जनविश्वास से निर्मित होती है। यदि व्यवस्थागत कमियां, निगरानी की विफलता, अपारदर्शिता या कथित मिलीभगत के प्रश्न उठ रहे हैं, तो उनका उत्तर केवल जांच रिपोर्ट नहीं दे सकती; उसका उत्तर कठोर जवाबदेही, संस्थागत सुधार और नैतिक आत्मशुद्धि से ही मिलेगा।

यह भी उतना ही सत्य है कि आरोप अंतिम सत्य नहीं होते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जांच पूरी होने और तथ्य सामने आने से पहले किसी को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा। लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हो तथा उसके निष्कर्ष जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखे जाएं।

राम भारतीय मानस में केवल आराध्य नहीं, बल्कि मर्यादा के सर्वोच्च प्रतिमान हैं। राम ने राज्य के लिए निजी सुख छोड़ा, वचन के लिए वनवास स्वीकार किया और न्याय के लिए स्वयं को कठोर अनुशासन में बांधा। यदि राम के नाम पर बनी व्यवस्थाएं भी उसी मर्यादा को आत्मसात करें, तभी राम मंदिर अपने पूर्ण अर्थ में राम का मंदिर कहलाएगा।

आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कितनी धनराशि का हिसाब अधूरा है, कितने लोग जांच के घेरे में हैं या किस पर क्या आरोप हैं। असली प्रश्न यह है कि—

क्या हमने राम का मंदिर बना लिया, लेकिन राम की मर्यादा को व्यवस्था का हिस्सा बनाना अभी बाकी है?

और शायद इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी सीख भी यही है कि राम केवल मंदिर में स्थापित करने का विषय नहीं हैं; राम को व्यवस्था, राजनीति, प्रबंधन और सार्वजनिक जीवन के आचरण में भी स्थापित करना होगा। क्योंकि यदि राम के नाम पर बनी व्यवस्था में भी माया, अपारदर्शिता और अविश्वास के प्रश्न उठने लगें, तो यह केवल एक संस्थागत संकट नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक नैतिक चेतना की परीक्षा बन जाता है। ■

पश्चिम बंगाल

'ब्रांड मोदी' और अमित शाह की रणनीतिक क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण

हर्ष कुमार

मई 2026 में घोषित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की। 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में 'ब्रांड मोदी', सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भाजपा की वैचारिक स्वीकार्यता का ऐतिहासिक विस्तार माना गया। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के साथ भाजपा ने उस राजनीतिक मिथक को तोड़ दिया कि पश्चिम बंगाल उसके लिए एक अभेद्य दुर्ग है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत और वैचारिक विजय

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का संबंध केवल वर्तमान राजनीति से नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक जड़ों से भी है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में कलकत्ता के ही महान राष्ट्रवादी नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा का यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

वर्ष 2026 जनसंघ की स्थापना के 75 वर्ष तथा डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती का कालखंड है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यह विजय केवल राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि डॉ. मुखर्जी की विचारधारा को उनकी जन्मभूमि में मिली स्वीकृति के रूप में भी देखी जा रही है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार को उनके वैचारिक स्वप्न की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

2014 से 2026 तक : संघर्ष से सत्ता तक

भाजपा का यह उभार किसी एक चुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि एक दशक से अधिक समय की रणनीतिक और संगठनात्मक यात्रा का प्रतिफल है।

2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 3 सीटें और 10.16 प्रतिशत वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 18 सीटें और 40.64 प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 77 सीटों तक पहुंची और पहली बार मजबूत विपक्ष बनी।

2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें घटकर 12 रह गईं, लेकिन इसी झटके ने भाजपा नेतृत्व को नई रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 45.84 प्रतिशत वोट शेयर और 207 सीटें हासिल कर दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया। वहीं टीएमसी का वोट शेयर घटकर 40.80 प्रतिशत रह गया और वह 80 सीटों पर सिमट गई।

93.71 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान यह संकेत था कि जनता बड़े राजनीतिक परिवर्तन की इच्छुक थी।

अमित शाह की रणनीति : चुनाव प्रबंधन की मास्टर क्लास

2026 की जीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका निर्णायक रही। 2024 के बाद उन्होंने बंगाल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और चुनाव से पहले लगातार 15 दिनों तक राज्य में रहकर अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने राज्य के 43 संगठनात्मक जिलों को पांच प्रमुख जोन में विभाजित किया तथा बूथ स्तर तक निगरानी व्यवस्था स्थापित की। इस दौरान 30 से अधिक जनसभाएं, रोड शो और सैकड़ों संगठनात्मक बैठकें आयोजित की गईं। भाजपा ने "प्रभारी-विस्तारक" मॉडल के तहत अन्य राज्यों के अनुभवी नेताओं को भी बंगाल में तैनात किया। अमित शाह का आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उन्होंने मतदान से पहले ही परिणामों को लेकर समयबद्ध भविष्यवाणी कर दी थी, जो लगभग सटीक साबित हुई।

भवानीपुर मॉडल : ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध

2026 चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ममता बनर्जी की भवानीपुर से हार रहा। भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से मैदान में उतारकर चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। रणनीति के तहत गुजराती और मारवाड़ी समुदायों सहित प्रभावशाली मतदाताओं से सीधा संवाद किया गया। मतदान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। प्रत्येक बूथ पर प्रशिक्षित प्रभारी नियुक्त किए गए और समर्थक मतदाताओं को सुबह 11 बजे तक मतदान कराने का लक्ष्य तय किया गया। इस सूक्ष्म प्रबंधन का परिणाम यह हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,105 मतों से पराजित कर दिया। नंदीग्राम में भी उन्होंने जीत दर्ज की।

मतदाता सूची संशोधन और विवाद

चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान चलाया गया, जिसके तहत लगभग 90 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। आयोग का तर्क था कि ये मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम थे।

हालांकि विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में वैध मतदाता भी सूची से बाहर कर दिए गए। वहीं भाजपा समर्थकों का दावा था कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनी।

सामाजिक मुद्दे और जनाक्रोश

आर.जी. कर और संदेशखाली का प्रभाव

महिला सुरक्षा 2026 चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गई। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की चिकित्सक के साथ हुई जघन्य घटना तथा संदेशखाली प्रकरण ने व्यापक जनाक्रोश पैदा किया। भाजपा ने आर.जी. कर पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने पानीहाटी सीट पर बड़ी जीत दर्ज की। इससे महिला मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भाजपा के पक्ष में लामबंद हुआ।

सीमावर्ती क्षेत्र, सीएए और मतुआ समुदाय

बांग्लादेश सीमा से लगे क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख चुनावी मुद्दे बने। 44 सीमावर्ती सीटों में भाजपा ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। मतुआ समुदाय ने भी बड़े पैमाने पर भाजपा का समर्थन किया, जिसे पार्टी की जीत का महत्वपूर्ण आधार माना गया।

सत्ता परिवर्तन और नई दिशा

9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति ने इस आयोजन को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया। नए मंत्रिमंडल में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निशिथ प्रमाणिक जैसे नेताओं को शामिल कर क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा सुरक्षा से जुड़े निर्णयों को मंजूरी देकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए।

निष्कर्ष : पूर्वी भारत में भाजपा का विस्तार

पश्चिम बंगाल में भाजपा की 2026 की विजय केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक संघर्ष की परिणति के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। 2014 से शुरू हुए 'ब्रांड मोदी' के विस्तार ने बंगाल में भी मजबूत राजनीतिक आधार स्थापित कर लिया। अमित शाह की सूक्ष्म रणनीति, शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व, महिला सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जनमत, तथा टीएमसी शासन के विरुद्ध बढ़ते असंतोष ने मिलकर इस परिणाम को संभव बनाया। अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक हिंसा को समाप्त करना, औद्योगिक विकास को गति देना और सुशासन स्थापित करना है। यदि सरकार इन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है, तो 2026 का यह जनादेश पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्थायी परिवर्तन का आधार सिद्ध हो सकता है। ■

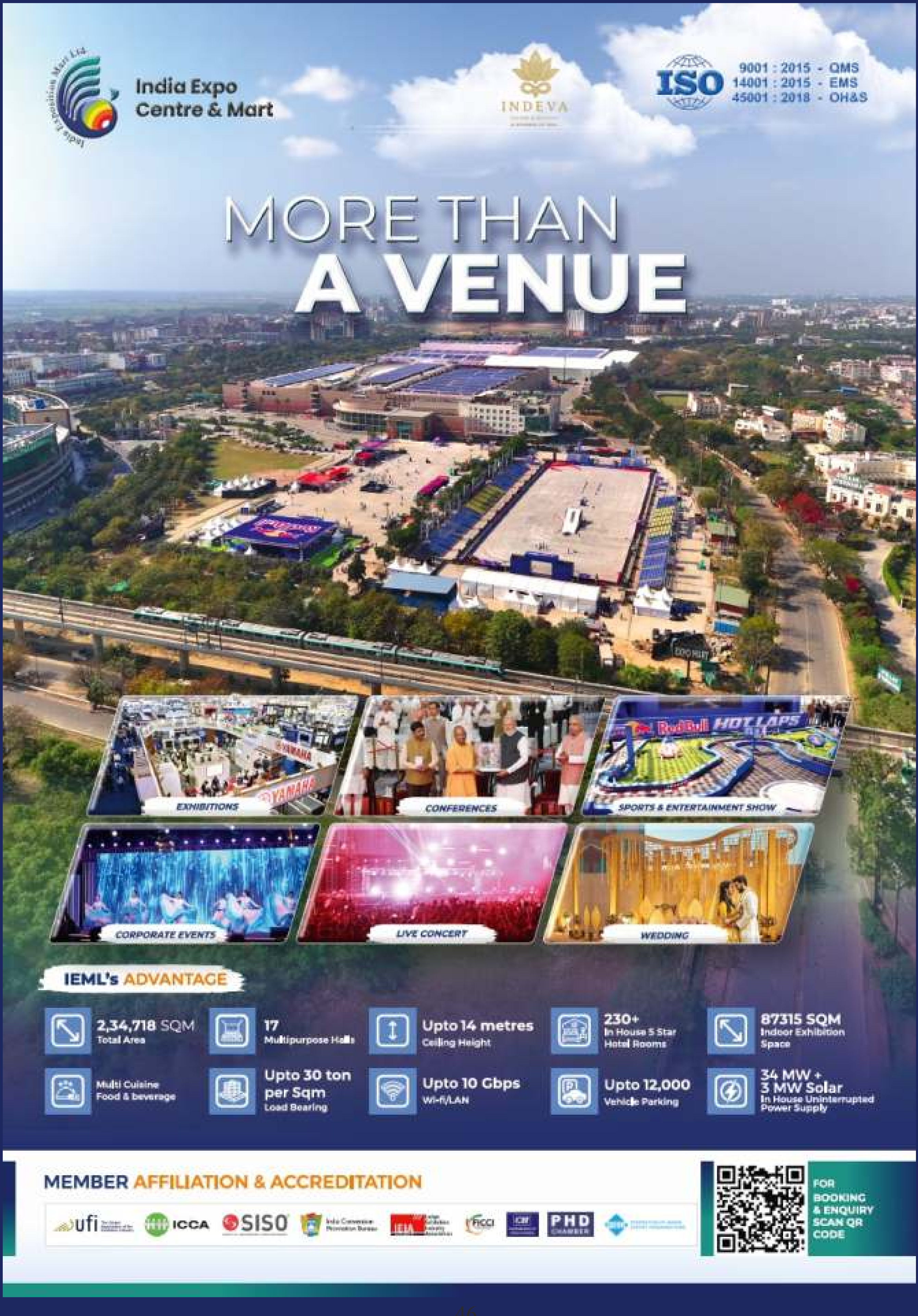
India Expo Centre & Mart
INDEVA
ISO
9001 : 2015 - QMS
14001 : 2015 - EMS
45001 : 2018 - OH&S
MORE THAN
A VENUE
EXHIBITIONS
CONFERENCES
SPORTS & ENTERTAINMENT SHOW
CORPORATE EVENTS
LIVE CONCERT
WEDDING
IEML's ADVANTAGE
2,34,718 SQM Total Area
17 Multipurpose Halls
Upto 14 metres Ceiling Height
230+ In House 5 Star Hotel Rooms
87315 SQM Indoor Exhibition Space
Multi Cuisine Food & beverage
Upto 30 ton per Sqm Load Bearing
Upto 10 Gbps Wi-fi/LAN
Upto 12,000 Vehicle Parking
34 MW + 3 MW Solar In House Uninterrupted Power Supply
MEMBER AFFILIATION & ACCREDITATION
ufi
ICCA
SISO
FICCI
PHD CHAMBER
FOR BOOKING & ENQUIRY SCAN QR CODE

अयोध्या की पिच पर सियासी मुकाबला

डॉ देवेंद्र कुमार शर्मा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली प्रतीक बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा ने इसे अपनी सबसे बड़ी वैचारिक और राजनीतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित किया है। ऐसे में अयोध्या से जुड़ा कोई भी विवाद या राजनीतिक बयान स्वतः ही राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन जाता है।

हाल के दिनों में श्रीराम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के आरोपों ने विपक्ष को भाजपा पर राजनीतिक हमला करने का अवसर दिया। समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दल इस मुद्दे को जवाबदेही और पारदर्शिता के सवाल से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो विपक्ष आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इसे भाजपा के खिलाफ एक प्रभावी चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम करता दिखाई देता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि उनकी सरकार बनने पर अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाया जाएगा।

पहली नजर में यह एक सामान्य राजनीतिक घोषणा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक व्यापक राजनीतिक संदेश छिपा था। यह संदेश था कि धार्मिक आस्था का मुद्दा अब केवल भाजपा का एकाधिकार नहीं है और समाजवादी पार्टी भी इस विमर्श में अपनी दावेदारी पेश करना चाहती है। लेकिन यहीं भाजपा ने अपनी राजनीतिक रणनीति बदल दी। हाथरस की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इसी बयान को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी पर तीखा वैचारिक हमला बोला। उन्होंने कहा, "अरे, आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, पहले अपना इतिहास देखिए।" इसके बाद उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन, कारसेवकों पर गोलीकांड, कांवड़ यात्रा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, मंदिरों के विकास और समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकारों के फैसलों को एक साथ जोड़ते हुए विपक्ष की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह वास्तव में धार्मिक आस्था का सम्मान करती है तो उसे मथुरा-वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से यह भाजपा की एक सोची-समझी रणनीति मानी जा सकती है। इससे बहस का केंद्र केवल अयोध्या नहीं रहता, बल्कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के व्यापक विमर्श में बदल जाता है, जहां भाजपा स्वयं को सबसे मजबूत मानती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अच्छी तरह समझती है कि यदि पूरा विमर्श केवल राम मंदिर से जुड़े आरोपों या प्रबंधन संबंधी विवादों तक सीमित रहा, तो विपक्ष उसे रक्षात्मक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। इसलिए पार्टी ने बहस का केंद्र बदलते हुए उसे इतिहास, आस्था, सांस्कृतिक विरासत और समाजवादी पार्टी के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड की ओर मोड़ने की कोशिश की है। इस आक्रामक राजनीतिक अभियान की कमान स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। यदि वह राम मंदिर से जुड़े सवालों को चुनावी मुद्दा बनाती है, तो उसे यह भी साबित करना होगा कि उसकी धार्मिक राजनीति केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता भी है। वहीं यदि भाजपा बहस को अयोध्या से मथुरा, काशी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर ले जाने में सफल रहती है, तो विपक्ष का मूल हमला कमजोर पड़ सकता है।

यही कारण है कि हाथरस का यह भाषण केवल एक चुनावी सभा का संबोधन नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक संघर्ष की दिशा तय करने वाला संकेत माना जा सकता है। एक ओर समाजवादी पार्टी अयोध्या और मंदिर से जुड़े मुद्दों के जरिए भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही तय करने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा अपनी वैचारिक बढ़त, हिंदुत्व के व्यापक विमर्श और विकास के एजेंडे के सहारे इस संभावित राजनीतिक नुकसान को सीमित करने का प्रयास करेगी।

आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि जनता किस नैरेटिव को अधिक विश्वसनीय मानती है—विपक्ष का जवाबदेही का सवाल या भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास का संयुक्त विमर्श। संभव है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की वैचारिक लड़ाई का पहला बड़ा अध्याय इसी बहस से लिखा जाए। ■

नए शीत युद्ध की आहट?

बारूद, प्रतिबंध और प्रॉक्सी संघर्षों के बीच क्या दुनिया एक नए वैश्विक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है?

"इतिहास स्वयं को हूबहू नहीं दोहराता, लेकिन उसकी प्रतिध्वनियां बार-बार सुनाई देती हैं।" —मार्क ट्वेन

सन् 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया ने सोचा था कि अब शांति का नया युग शुरू होगा। लेकिन युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि विश्व दो ध्रुवों में बंट गया—एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी ओर सोवियत संघ। अगले लगभग पैंतालीस वर्षों तक पूरी दुनिया एक ऐसे संघर्ष की साक्षी बनी, जिसमें युद्ध का भय हर समय मौजूद था, लेकिन महाशक्तियां प्रत्यक्ष युद्ध से बचती रहीं। इस कालखंड को इतिहास ने "शीत युद्ध" (Cold War) का नाम दिया।

आज, इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में खड़े होकर जब हम मध्य पूर्व, यूक्रेन, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों की राजनीति को देखते हैं, तो एक प्रश्न बार-बार उभरता है—क्या दुनिया एक नए शीत युद्ध, बल्कि "तृतीय शीत युद्ध" की ओर बढ़ रही है? यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सभ्यतागत, आर्थिक और मानवीय चिंता का विषय है।

शीत युद्ध : इतिहास का सबसे लंबा तनाव

पहला शीत युद्ध (1947-1991) दो विचारधाराओं का संघर्ष था—पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में नहीं भिड़े, लेकिन दुनिया के अनेक क्षेत्र उनके संघर्ष के अखाड़े बन गए। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, सोवियत - अफगान युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, जैसे घटनाक्रम इस बात के प्रमाण हैं कि शीत युद्ध कभी वास्तव में "शीत" नहीं था; उसकी आग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लगातार जलती रही।

सन् 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। उस समय कई विद्वानों ने इसे इतिहास का अंत और उदार लोकतंत्र की अंतिम विजय घोषित कर दिया था। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता।

नया शीत युद्ध : विचारधारा नहीं, हितों का संघर्ष

इक्कीसवीं सदी का नया वैश्विक तनाव पहले शीत युद्ध से अलग है। इस बार संघर्ष केवल पूंजीवाद और साम्यवाद का नहीं है, बल्कि— अमेरिका की वैश्विक प्रभुत्ववादी व्यवस्था, चीन और रूस की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आकांक्षा, मध्य पूर्व में शक्ति-संतुलन, ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, तकनीकी वर्चस्व, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर प्रतिस्पर्धा, तथा भू-राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रों की लड़ाई का है। दुनिया फिर से दो नहीं, बल्कि कई शक्ति-केंद्रों में विभाजित होती दिखाई दे रही है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका : नए शीत युद्ध की धधकती प्रयोगशाला

मध्य पूर्व आज वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील भूभाग बन चुका है। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजरायल की सुरक्षा चिंताएं, अमेरिका की रणनीतिक प्रतिबद्धताएं, लाल सागर की समुद्री सुरक्षा, तेल आपूर्ति और प्रॉक्सी समूहों की गतिविधियां—ये सभी तत्व मिलकर वैश्विक तनाव को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं।

युद्ध भले प्रत्यक्ष न हो, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले, खुफिया अभियानों, ड्रोन युद्ध, प्रॉक्सी संगठनों, और सूचना युद्ध के माध्यम से संघर्ष निरंतर जारी है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है, जैसे शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियां तीसरे देशों के माध्यम से अपने हित साधती थीं।

मध्य एशिया : नई "ग्रेट गेम" का केंद्र

उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच मध्य एशिया को लेकर चली प्रतिस्पर्धा को इतिहास में "ग्रेट गेम" कहा गया।

आज वही क्षेत्र पुनः वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है। कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान

और और ताजीकिस्तान ऊर्जा, खनिज संसाधनों और रणनीतिक स्थिति के कारण विश्व शक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं।

यह क्षेत्र आज- रूस की सुरक्षा नीति, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, अमेरिका की रणनीतिक रुचि, तुर्किये की सांस्कृतिक सक्रियता, और ईरान की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन का मैदान बन चुका है।

नया शीत युद्ध : बंदूक से अधिक डेटा का युद्ध

पहले शीत युद्ध में हथियारों की दौड़ थी। आज— कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, 5जी नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, उपग्रह प्रणाली, और डिजिटल मुद्राएं नए हथियार बन चुके हैं। यह "मिसाइलों का युद्ध" कम और "माइक्रोचिप्स का युद्ध" अधिक है। यदि बीसवीं सदी में परमाणु बम शक्ति का प्रतीक था, तो इक्कीसवीं सदी में डेटा और तकनीक सामरिक शक्ति का नया मानक बन चुके हैं।

दुनिया फिर गुटों में बंट रही है। नाटो (North Atlantic Treaty Organization) का विस्तार (हालांकि अमेरिका ईरान और इजरायल युद्ध में नाटो की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हुए), BRICS का उभार, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की चर्चा, डॉलर के विकल्प की तलाश, और वैश्विक दक्षिण की बढ़ती आवाज—ये सभी संकेत एक नए वैश्विक पुनर्संरचना की ओर इशारा करते हैं।

पहले शीत युद्ध में दुनिया दो ध्रुवों में बंटी थी। आज दुनिया - अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, भारत, मध्य पूर्व की क्षेत्रीय शक्तियों, जैसे अनेक केंद्रों में विभाजित होती दिखाई दे रही है। इसे कुछ विद्वान "मल्टीपोलर कोल्ड वॉर" (बहुध्रुवीय शीत युद्ध) भी कह रहे हैं। क्या तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा है? इतिहास बताता है कि शीत युद्धों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे अक्सर प्रत्यक्ष विश्वयुद्ध को टालते हुए भी निरंतर युद्धों को जन्म देते हैं। आज भी यही स्थिति है।

विश्व शक्तियां प्रत्यक्ष परमाणु टकराव से बचना चाहती हैं, लेकिन— प्रॉक्सी युद्ध, आर्थिक युद्ध, साइबर युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध, समुद्री तनाव, और सूचना युद्ध दुनिया को लगातार अस्थिर बना रहे हैं। अर्थात् मानवता शायद तीसरे विश्वयुद्ध में नहीं, बल्कि "लगातार चलने वाले सीमित संघर्षों के युग" में प्रवेश कर रही है।

भारत के लिए क्या मायने?

भारत के लिए यह दौर अवसर और चुनौती दोनों है। भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से रणनीतिक स्वायत्तता की रही है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। आज भी भारत किसी एक ध्रुव का हिस्सा बनने के बजाय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि— ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे, पश्चिम एशिया में भारतीय हित सुरक्षित रहें, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में उसकी भूमिका बढ़े, और वह महाशक्तियों के संघर्ष में फंसने से बच सके।

क्या हम वास्तव में तृतीय शीत युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं?

इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। दुनिया अभी औपचारिक रूप से तीसरे शीत युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती। लेकिन यदि शीत युद्ध को इस रूप में परिभाषित करें कि—

"जब महाशक्तियां प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए आर्थिक, तकनीकी, सामरिक और प्रॉक्सी संघर्षों के माध्यम से वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करें,"

तो निस्संदेह दुनिया उसी दिशा में बढ़ती दिखाई देती है।

पुरानी कहावत है—

"जब हाथियों की लड़ाई होती है, तो घास ही सबसे अधिक कुचली जाती है।"

आज भी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा मूल्य छोटे देश, गरीब समाज और सामान्य नागरिक चुका रहे हैं।

अंतिम प्रश्न

बीसवीं सदी का शीत युद्ध बर्लिन की दीवार के गिरने पर समाप्त हुआ था। इक्कीसवीं सदी का नया शीत युद्ध शायद किसी दीवार के गिरने से नहीं, बल्कि विश्वास, वैश्विक सहयोग और संतुलित बहुध्रुवीय व्यवस्था के निर्माण से समाप्त होगा। लेकिन फिलहाल विश्व जिस दिशा में बढ़ रहा है, वहां शांति की भाषा कमजोर और शक्ति की भाषा अधिक मुखर दिखाई दे रही है और इसलिए यह प्रश्न पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है—

क्या मानवता तीसरे विश्वयुद्ध से बचने के प्रयास में अनजाने ही "तृतीय शीत युद्ध" के लंबे, जटिल और अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है? ■

KDMG
DESIGN. BUILD. INSPIRE
आँखें खोलो, फिर विश्वास करो।
राजनगर एक्सटेंशन के बीचों-बीच
GDA APPOVED
एक बार आइयेगा जरूर!
KDMG
central
point
RAJNAGAR EXTN. GHAZIABAD
READY FOR FIT-OUT
KDMG DEVELOPERS & PROMOTERS
Khasra No. 966-967, Raj Nagar Extn., Ghaziabad, U.P. (NCR) - 201 017
W : www.kdmg.in E: info@kdmg.in
7532 040404

KDMG
DESIGN. BUILD. INSPIRE.
आँखें खोलो, फिर विश्वास करो।
लक्ज़री सुइट्स. प्रीमियम लाइफस्टाइल.
AUTHORITY APPOVED
KDMG
THE WHITE DOOR
SUITES
Greater Noida West
ANALOX TOWN PLANNERS PVT. LTD. (An ISO 9001, 14001 & 45001 Certified Company)
Trilokpuram Greens, Site C, Residential Pocket, Near Tilapta Chowk,
Greater Noida West, Gautam Buddh Nagar, U.P.(NCR)-201 306.
W : www.kdmg.in E: info@kdmg.in (CIN-U70100DL2014PTC265610)
7532 040404

Yogi Adityanath
Chief Minister, Uttar Pradesh

Shape the Future of Healthcare and Education in Greater Noida

Nand Gopal Gupta 'Nandi'
Minister of Industrial Development
Uttar Pradesh

Jaswant Saini
Minister of State for
Industrial Development
Uttar Pradesh

Scheme for Institutional Plots through e-Auction Online

Bidding Scheme Code: INS01/2026

SALIENT FEATURES

• Proximity to Noida International Airport • Easy access to Eastern & Western Dedicated Freight Corridors • Best planned city in NCR • Expressways providing excellent Multi-city Connectivity • Residential Sectors, Commercial Sectors, Educational Institutions in the Vicinity • World-class civic amenities

GNIDA announces e-Auction for the allotment of Institutional Plots, as per terms and conditions prescribed in the on-line brochure.

How to Participate/Other details: Interested parties will need to signup and obtain user ID and password on the portal **https://gnida.etender.sbi** as well as deposit documents. Processing Fee (Participation Fee) & EMD separately through online payments as per date mentioned in the online brochure.

The brochure containing details of Plots, procedures, terms & conditions of e-Auction is available on our website **www.greaternoidaauthority.in** and the web portal **https://gnida.etender.sbi** It will be the sole responsibility of the bidder/ participant to obtain a compatible computer terminal with internet connection to enable him/her to participate in the e-bidding process any reasons thereof. Authority reserve the right to accept or reject one or all the bids or cancel/postpone the e-auction without assigning any reason.

INSTITUTIONAL PLOTS SCHEME

Sl. No.	Plot No.	Sector	Area of Plot (in Sqm.)	Use of Plots	Total Reserve Price (in ₹)
1	HO-02	Mu	10005	Hospital	38,25,71,190/-
2	HO/01	Zeta-I	6880	Hospital	27,65,89,760/-
3	H.0-02	Zeta-I	3050	Hospital	14,94,56,100/-
4	F-02	P-5, Builders Area	598	Hospital Facility	2,70,92,988/-
5	11 B	BETA -2	493.40	Nursing Home	2,26,46,073/-
6	N.H.-1	Sector-Eta-1	5167	Nursing Home	21,80,47,400/-
7	85-86	K.P-5	4002	Paramedical Institute	12,14,92,000/-
8	204/3	K.P-5	840	Paramedical Institute	2,61,35,760/-
9	53/3	K.P-5	1065	Vocational Training/ Educational Institute	3,31,36,410/-

Note: *The area of plot allotted may slightly vary at the time of handing over of the possession. The premium of the plot will proportionately vary due to such variation.*

Plots clear from all encumbrances | Allotment will be made on "as is where is basis" | Plot ready for Possession

Brochure Download & Registration Starts	Registration End Date	Last Date of EMD, Processing Fee Deposit	Last Date of Final Submission of Document	E-Auction Date & Time to be Notified Separately
22.06.2026 | 3:00 PM	13.07.2026 | 5:00 PM	15.07.2026 | 5:00 PM	17.07.2026 | 5:00 PM	

For corrigendum/addendum, Please refer to website **www.greaternoidaauthority.in**
Don't miss the opportunity, please visit **One Map Greater Noida** for plots location details.

Greater Noida Industrial Development Authority
Plot No. 01, Knowledge Park-04, Greater Noida-201308, Distt.-Gautam Budh Nagar, (U.P.)
Helpline Center No.: 0120-2336046, 2336047, 2336048, 2336049
Ph.: 0120-2336030-33 | E-mail: authority@gnida.in | Website: www.greaternoidaauthority.in

Follow us on
/OfficialGNIDA